@saahassamachar @saahassamachar @saahassamachar

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

राष्ट्रीय संस्करण

साहस समाचार

निष्पक्ष, निर्भीक, बेबाक

नई दिल्ली, शुक्रवार, 31 जुलाई 2026, वर्ष-1, अंक-248, पृष्ठ-8, मूल्य-2 रुपए RNI No-DLHIN/25/A2841 www.saahassamachar.in

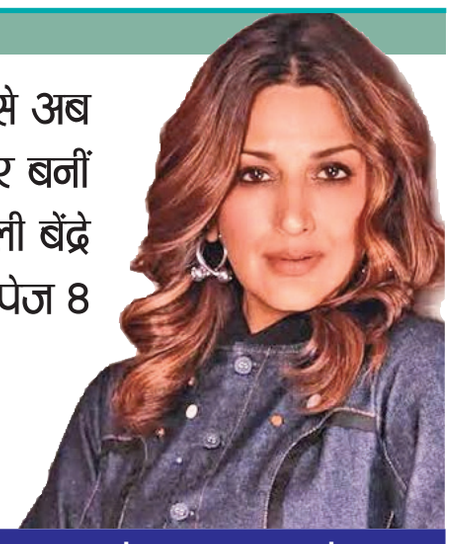

एक्ट्रेस से अब प्रेजेंटर बनीं सोनाली बेंद्रे ... पेज 8

सरकार ने ई20 ईंधन को वाहनों के लिए सुरक्षित बताया

नई दिल्ली,एजेंसी।

सरकार ने अपने एथनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम का बचाव करते हुए कहा कि बड़े पैमाने पर परीक्षणों और व्यापक रूप से उपयोग में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि ई20 पेट्रोल (20 प्रतिशत एथनॉल मिश्रित पेट्रोल) से इंजन में असामान्य नुकसान पहुंचने, जंग लगने या वाहनों की आयु कम होने की समस्या आती है। सरकार ने कहा कि एथनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया है और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव से उपभोक्ताओं को राहत देने में मदद की है।

लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि एथनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम को नीति आयोग, वाहन विनिर्माताओं, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई), सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम), तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) और अन्य तकनीकी संस्थानों के साथ परामर्श कर चरणबद्ध एवं वैज्ञानिक तरीके से लागू किया गया है।

उन्होंने कहा कि एआरएआई, सियाम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी), भारतीय पेट्रोलियम संस्थान और वाहन विनिर्माताओं द्वारा

किए गए प्रयोगशाला अध्ययन और क्षेत्रीय परीक्षणों से पुष्टि हुई है कि निर्धारित मानकों के तहत ई20 ईंधन का उपयोग सुरक्षित है। गोपी ने कहा, इन अध्ययनों से यह भी पता चला है कि पुराने वाहनों के प्रदर्शन में ई20 के कारण कोई महत्वपूर्ण बदलाव या इंजन में असामान्य नुकसान देखने को नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि प्रयोगशाला अध्ययन, क्षेत्रीय सत्यापन और वास्तविक उपयोग में वाहनों के प्रदर्शन पर व्यापक प्रतिकूल प्रभाव का कोई प्रमाण नहीं मिला है।

सरकार ने कहा कि व्यापक स्तर पर, 'ई15प्लस' पेट्रोल (15 प्रतिशत एथनॉल मिश्रित पेट्रोल) का इस्तेमाल साढ़े तीन साल से अधिक समय से और 'ई19-ई20' (19/20 प्रतिशत एथनॉल मिश्रित पेट्रोल) ईंधन का उपयोग ढाई साल से अधिक समय से हो रहा है। उसने कहा कि 20 करोड़ से अधिक दोपहिया वाहन और तीन करोड़ से अधिक पेट्रोल कारें इन मिश्रित ईंधनों के जरिये परिचालित हो रही हैं, लेकिन एथनॉल मिश्रण के कारण व्यापक स्तर पर इंजन खराब होने या वाहनों के बड़े पैमाने पर खराब होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है।

मंत्री ने कहा कि वाहन विनिर्माताओं के आंकड़ों से भी ई20 ईंधन के कारण इंजन को असामान्य नुकसान पहुंचने, उनमें जंग लगने या वाहन की आयु घटने की बात सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि विनिर्माता ई20 ईंधन का उपयोग करने वाले वाहनों के लिए वारंटी दायित्वों को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक प्रमुख वाहन विनिर्माता ने वर्ष 2025-26 में 2.84 करोड़ वाहनों की 'सर्विसिंग' की, जिनमें करीब 1.5 करोड़ ऐसे वाहन शामिल थे जो मूल रूप से ई20 के अनुरूप प्रमाणित नहीं थे। उसने ई20 के कारण इंजन में जंग लगने, उसे असामान्य नुकसान पहुंचने या कलपुर्जों की आयु घटने की कोई समस्या नहीं बताई।

गोपी ने कहा कि एक प्रमुख दोपहिया वाहन विनिर्माता ने भी इसी तरह का अनुभव साझा किया है, जबकि एक अन्य वाहन विनिर्माता ने लंबे समय तक 1.4 करोड़ ई20 आधारित वाहनों की निगरानी के बाद एथनॉल के कारण इंजन में जंग लगने का कोई प्रमाण नहीं पाया। सरकार ने कहा कि ई20 ईंधन अधिक 'ऑक्टेन', बेहतर 'एंटी नॉक' प्रदर्शन, बेहतर दहन उपलब्ध करता है, गति सुचारु होती है और उत्सर्जन में कमी आती है। इससे इंजन का संचालन अधिक स्वच्छ और प्रभावी होता है।

सार समाचार

नीली नहीं अब विश्व कप में भगवा जर्सी पहनेंगी भारतीय हॉकी टीमें

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय पुरूष और महिला हॉकी टीमें अगले महीने नीदरलैंड और बेल्जियम में होने वाले एफआईएच विश्व कप में पारंपरिक नीली जर्सी नहीं बल्कि केसरिया रंग की जर्सी पहनेगी । जर्सी का रंग बदलने के इस फैसले पर विवाद के बाद हॉकी इंडिया ने कहा है कि कोचों और खिलाड़ियों के अनुरोध पर तकनीकी कारणों से यह फैसला लिया गया है । इस फैसले पर हालांकि पूर्व कप्तान वीरेन रासकिन्हा ने सवाल उठाते हुए कहा है कि हॉकी टीम बरसों से नीली जर्सी में खेलती आई है और प्रशंसक भी उसे इसी रंग में देखना चाहते हैं। विवाद के बाद हॉकी इंडिया ने एक बयान में कहा, यह देखा गया कि नीली जर्सी नीले रंग की एस्ट्रो टर्फ (मैदान की सतह) के साथ घुल-मिल जाती थी जबकि अंतरराष्ट्रीय हॉकी पिचों के लिए नीला रंग ही अब मानक है। इस एक जैसे रंग की वजह से खिलाड़ियों को मैदान पर साफ देखने में दिक्कत होती थी। इसमें कहा गया कोचों और खिलाड़ियों ने पीले या केसरिया जैसे दूसरे रंगों का सुझाव दिया। अच्छी तरह सोच विचार के बाद केसरिया रंग को चुना गया।

प्रौद्योगिकी में देरी, तकनीक से वंचित होने के समान : वायुसेना प्रमुख

नई दिल्ली, एजेंसी। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए. पी. सिंह ने बृहस्पतिवार को पायलट रहित हवाई प्रणाली और दूसरी जरूरी रक्षा प्रौद्योगिकी बनाने में ज्यादा आत्मनिर्भरता हासिल करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी में देरी का मतलब है तकनीक न मिलना और ऐसी चीज का कोई फायदा नहीं है जो दूसरों के पास पहले से आ जाने के बाद मिले। यहां एक कार्यक्रम में अपने संबोधन में उन्होंने यह भी कहा कि हमारे और नागरिक उड्डयन मंत्रालय तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों के बीच बातचीत जारी है" ताकि हम किसी ड्रोन की पहचान कर सकें कि वह असली ड्रोन है या कोई अवैध (दुश्मन/खतरनाक) ड्रोन।

सरकार और युवाओं के बीच विश्वास अहम : वांगचुक

नई दिल्ली, एजेंसी। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने संसद में 'लोक परीक्षा (संशोधन) विधेयक' पेश किए जाने का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि इससे देश की शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार होंगे। उन्होंने साथ ही सरकार से अपील की कि वह हाल के विरोध प्रदर्शनों में शामिल छात्रों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई न करने के अपने लिखित वादे का सम्मान करे।

दिल्ली में संपत्तियों का बनेगा प्रॉपर्टी आधार कार्ड: दिल्ली सरकार

नई दिल्ली, एजेंसी।

दिल्ली सरकार भूमि रिकॉर्ड विधेयक, 2026 तैयार कर रही है और शहर में प्रत्येक संपत्ति के लिए 'संपत्ति आधार कार्ड' पेश करने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। बयान में कहा गया है कि इस विधेयक के कानून बनने के बाद पूरी दिल्ली की प्रत्येक संपत्ति का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर उसका डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा और इसके बाद प्रत्येक संपत्ति के लिए एक विशिष्ट 'प्रॉपर्टी आधार कार्ड' बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जिस प्रकार आधार कार्ड ने प्रत्येक नागरिक की पहचान को एक विश्वसनीय स्वरूप प्रदान किया है, उसी प्रकार अब दिल्ली की प्रत्येक संपत्ति की भी एक प्रमाणिक और सुरक्षित डिजिटल पहचान सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे राजधानी में संपत्तियों के रिकॉर्ड पारदर्शी, व्यवस्थित और तकनीकी रूप से सुरक्षित बनेंगे। गुप्ता ने कहा कि इस विधेयक को लेकर सरकार अलग से विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाएगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार पहले चरण में केंद्र सरकार की 'स्वामित्व' योजना के तहत 30 ग्रामीण गांवों में आधुनिक तकनीक और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से ड्रोन सर्वेक्षण कर स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड तैयार कर चुकी है। गुप्ता ने कहा कि प्रस्तावित 'दिल्ली भूमि रिकॉर्ड विधेयक, 2026' के तहत केवल गांव ही नहीं, बल्कि शहरी क्षेत्रों की प्रत्येक आवासीय, व्यावसायिक एवं अन्य प्रकार की संपत्तियों का भी विस्तृत सर्वेक्षण किया जाएगा।

प्रधानमंत्री दो अगस्त को नशे के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी अभियान छेड़ेंगे: मांडविया

नई दिल्ली,एजेंसी। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बृहस्पतिवार को कहा कि युवाओं में नशीले पदार्थों की लत की समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दो अगस्त को 100 सप्ताह तक चलने वाले देशव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत करेंगे। मांडविया ने राज्यसभा में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान' नामक इस अभियान में खेल प्रतियोगिताएं, वॉकथॉन, ध्यान सत्र, नुक्कड़ नाटक जैसी साप्ताहिक गतिविधियां शामिल होंगी।

उन्होंने कहा, दो अगस्त को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश को संबोधित करेंगे और एक करोड़ से अधिक युवा 'नशा मुक्ति' की शपथ लेंगे, जिसमें वे नशा-मुक्त रहने और दूसरों को भी नशा-मुक्त रहने में मदद करने के अपने संकल्प को दोहराएंगे।

राज्यसभा ने दी प्रश्नपत्र लीक निरोधक विधेयक को मंजूरी

सदन ने विपक्ष द्वारा विधेयक पर लाये गये संशोधन प्रस्तावों को ध्वनिमत से खारिज कर दिया

नई दिल्ली, एजेंसी।

राज्यसभा ने बृहस्पतिवार को 'लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026' को मंजूरी दे दी और इसके साथ ही विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गयी जिसमें प्रश्न पत्र लीक करने के अपराध में दस साल तक की सजा तथा 50 लाख रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। नीट प्रश्नपत्र लीक की पृष्ठभूमि में लाए गए लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 को लोकसभा ने एक दिन पहले ही मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया और उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी।

सदन ने विपक्ष द्वारा विधेयक पर लाये गये संशोधन प्रस्तावों को ध्वनिमत से खारिज कर दिया। मंत्री के जवाब के पहले कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए सदन से वाक आउट किया। वाक आउट पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष पूरी तरह से मुद्दाविहीन हो गया है और उसने अपनी करतूत से इसे साबित भी कर दिया है। चर्चा का जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह विधेयक सिर्फ पेपर लीक से नहीं जुड़ा हुआ है बल्कि परीक्षा में कदाचार से जुड़े विभिन्न पहलुओं को भी शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक सिर्फ एनटीए ही नहीं, बल्कि यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी परीक्षाओं को भी कवर करता है।

उन्होंने छात्रों से जुड़े विषयों का जिक्र करते हुए कहा कि यह ऐसा मुद्दा है जो हर भारतीय नागरिक को प्रभावित करता है, यह विषय देश के हर परिवार, हर अभिभावक से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जिस विकसित भारत 2047 का जिक्र करते हैं, उसके लिए ये युवा और छात्र बहुत बड़े निवेश हैं। उन्होंने चर्चा में विभिन्न विपक्षी सदस्यों द्वारा पेश किए गए आंकड़ों की सत्यता को लेकर सवाल किया। उन्होंने कहा कि चर्चा में जिक्र किया गया कि प्रश्नपत्र लीक के 152 मामले सामने आए हैं। उन्होंने सवाल किया कि ये आंकड़े कहां से मिले, यह बताना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चर्चा में कहा गया कि भारत में प्रभावित बच्चों की संख्या करोड़ों में बतायी गयी जो अवास्तविक है।

सिंह ने शिक्षा में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा लायी गयी नयी शिक्षा नीति से स्थिति में व्यापक बदलाव आया और बच्चों को अपना पसंदीदा विषय चुनने की व्यापक आजादी मिली। उन्होंने कहा कि पहले छात्रों को विषयों के चुनाव में सीमित विकल्प मिलते थे और स्थिति में बदलाव बहुत पहले किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सरकार ने मेडिकल शिक्षा को वहनीय बनाने पर जोर दिया और मैनेजमेंट कोटा व्यवस्था को खत्म किया।

उन्होंने कहा कि सरकार ने सीटों में वृद्धि करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने न सिर्फ मेडिकल शिक्षा में बल्कि उच्च शिक्षा पर जोर दिया है और विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने लंबित रिक्तियों और प्रोन्नति का भी जिक्र किया और कहा कि बड़े पैमाने पर कर्मियों को प्रोन्नति दी गयी।

लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 के प्रावधानों के अनुसार परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम पांच साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास तथा 50 लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा हो सकती है।

इसी तरह संगठित अपराधों के लिए कम से कम सात साल के कारावास और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत सभी जांच दो महीने के भीतर पूरी करनी होंगी।

एनटीए को भंग करने की राज्यसभा में उठी मांग

नई दिल्ली,एजेंसी। राज्यसभा में बृहस्पतिवार को विपक्ष के कई सदस्यों ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को भंग करने की मांग करते हुए कहा कि यह नीट सहित विभिन्न परीक्षाएं आयोजित करने में नाकाम रही है। राज्यसभा में 'लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026' पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कई सदस्यों ने परीक्षा सुधारों की जरूरत पर बल दिया। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सदस्य मनोज कुमार झा, समाजवादी पार्टी (सपा) के राम गोपाल यादव सहित कई सदस्यों ने एनटीए को भंग करने की मांग की।

सपा सदस्य यादव ने कहा कि एनटीए में कुल 39 स्वीकृत पद हैं और उनमें से 15 खाली हैं। उन्होंने कहा कि 73 कर्मचारी संविदा पर हैं और 124 आउटसोर्सिंग के आधार पर काम कर रहे हैं। यादव ने कहा कि एनटीए के अस्थायी कर्मियों में ज़्यादा ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं है। उन्होंने केंद्र को सुझाव दिया कि वह राज्यों को पहले की तरह मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दे। विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) सदस्य महुआ माजी ने कहा कि अगर सज़ा और जुर्माना बढ़ाने से अपराध रुक सकते, तो इस दुनिया में कोई अपराध नहीं होता।

छात्रों पर बलप्रयोग की न्यायिक जांच हो: खरगे

नई दिल्ली, एजेंसी।

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रश्न पत्र लीक मामलों को रोकने के लिए सरकार द्वारा लाये गये विधेयक के भविष्य में कारगर होने पर आशंका जताते हुए एक समयबद्ध वार्षिक परीक्षा कैलेंडर बनाये जाने का सुझाव दिया तथा हाल में हुए छात्र आंदोलन में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई ज्यादतियों की न्यायिक जांच कराने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष ने लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पर उच्च सदन में चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि सरकार ने इस विधेयक में कड़े प्रावधान किये हैं किंतु उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि फर्क इससे पड़ेगा कि आप परीक्षाएं कैसे कराते हैं और प्रश्न पत्र लीक होने से कैसे रोक पाते हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार से सवाल किया कि वह इस समय जो काम कर रही है उसने दो साल पहले मूल कानून बनाते समय ही इस काम को क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने युवाओं के मामले को उठाते हुए इस कानून की खामियों को उजागर किया था। खरगे ने कहा कि यह विधेयक अभी भी अधूरा है तथा इससे प्रश्न पत्र लीक होने को नहीं रोका जा सकेगा। उन्होंने कहा कि आजकल जो माहौल चल रहा है, उसे ठंडा करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी सड़कों पर उतरे, उन्हें शांत कराने के लिए यह विधेयक लाया गया है।

उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों के आगे घुटने टेकने पड़े तथा प्रधानमंत्री को (शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र) प्रधान को हटाना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि सरकार को अपनी सत्ता जाने का डर सताने लगा, इसलिए यह काम किया गया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में जो प्रदर्शन किया, उससे सरकार डर गयी और इसीलिए उसने प्रधान से इस्तीफा लेने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी कुर्सी (को बचाने) के लिए यह सब किया।

उन्होंने इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इस मामले में कुछ भी नहीं कहे जाने पर प्रश्न उठाये। उन्होंने प्रश्न किया कि गृह मंत्री चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? उन्होंने सरकार को आगाह किया कि छात्रों ने सरकार को जो सबक सिखाया है, उससे कई गुना बड़ा सबक वे फिर सिखा सकते हैं।

धार में भोजशाला परिसर के पास दरगाह की जमीन पर जुमे की नमाज़ पढ़ने की इजाजत : न्यायालय

भोजशाला : दरगाह की जमीन पर जुमे की नमाज पढ़ने की अनुमति

नई दिल्ली, एजेंसी।

उच्चतम न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष को मध्य प्रदेश के धार में विवादित भोजशाला परिसर से सटी दरगाह के परिसर में शुक्रवार की नमाज अदा करने की इजाजत दे दी।

न्यायालय ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि मुसलमानों को शुक्रवार को अपराह्न एक बजे से तीन बजे के बीच उस जगह पर नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने हालांकि कहा कि इस निर्देश का मतलब यह नहीं है कि राज्य सरकार और मुस्लिम पक्ष आपसी सहमति से शुक्रवार की नमाज के लिए कोई दूसरी जगह नहीं तलाश सकते।

पीठ ने 14 जुलाई को निर्देश दिया था कि जब तक मामले का फैसला नहीं हो जाता तब तक धार में विवादित जगह के पास शुक्रवार को अपराह्न एक बजे से तीन बजे के बीच नमाज के लिए एक अलग खुली जगह उपलब्ध कराई जाए।

बाद में, हाजी मुनीर अहमद की अगुवाई में मुस्लिम पक्ष ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया और आरोप लगाया कि वैकल्पिक जगह देने के अदालत के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है; उनका कहना था कि धार प्रशासन जो जगह दे रहा था, वह विवादित भोजशाला परिसर से 1.3 किलोमीटर दूर थी।

उन्होंने कहा कि जगह इतनी पास होनी चाहिए कि मुसलमान नमाज पढ़ते समय मस्जिद को देख

सकें। मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी और राज्य सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज की दलीलें सुनने के बाद, 14 जुलाई के पिछले आदेश को स्पष्ट किया गया।

सीजेआई ने एक आदेश में कहा, पहले के आदेश को इस हद तक स्पष्ट किया गया है कि मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार को अपराह्न एक से तीन बजे के बीच खसरा नंबर 596 वाली जमीन पर नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए; यह जमीन दरगाह की जमीन बताई जाती है। स्थल योजना की पेश की गई प्रति से पता चलता है कि यहां आने-जाने के लिए एक स्वतंत्र और अलग रास्ता है, इसलिए यह स्थल उपयुक्त लगता है। यह संबंधित परिसर से सटा हुआ है। पीठ ने कहा, यह आदेश दोनों पक्षों को आपसी सहमति से किसी अन्य जगह को चुनने से नहीं रोकता है। सुनवाई के दौरान अहमदी ने कहा कि भोजशाला परिसर से सटे उपयुक्त वक्फ भूखंड उपलब्ध हैं, लेकिन राज्य प्रशासन कानून-व्यवस्था का हवाला देकर उन्हें देने से इनकार कर रहा है। उन्होंने कहा, आप गलत काम करने वाले के सामने झुक नहीं सकते। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को फैसला सुनाया कि धार जिले में विवादित भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद परिसर देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है।

साथ ही, इसने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के दशकों पुराने उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसके तहत मुस्लिम समुदाय को उस जगह पर शुक्रवार की नमाज़ पढ़ने की इजाजत दी गई थी।

उच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि केंद्र और एएसआई भोजशाला परिसर के प्रशासन और प्रबंधन के बारे में फैसला ले सकते हैं।

वंदे मातरम के अपमान को दंडनीय बनाने के प्रावधान वाले विधेयक को संसद की मंजूरी

नई दिल्ली, एजेंसी।

संसद ने बृहस्पतिवार को उस विधेयक को पारित कर दिया, जिसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए तीन वर्ष तक की सजा हो सकती है। राष्ट्रगान 'जन गण मन' के साथ ही उसी सम्मान के साथ राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' के गायन को अनिवार्य बनाने वाले 'राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026' को लोकसभा ने बृहस्पतिवार को द्रमुक समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के बीच संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी।

इससे पहले उच्च सदन ने बुधवार को विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी। प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर में 'चढ़ावा चोरी' जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की बैठक दो बार के स्थगन के बाद अपराह्न साढ़े तीन बजे शुरू हुई तो विपक्षी सांसद पहले की तरह ही नारेबाजी कर रहे थे। हंगामे के बीच ही विधेयक पर सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इस विधेयक के पारित होने के बाद राष्ट्रगीत को वही सम्मान मिलेगा जो राष्ट्रगान को मिलता है। उन्होंने कहा कि 'वंदे मातरम' एक भारत-श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत के संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने द्रमुक सांसदों की चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है जो किसी राज्य, किसी व्यक्ति व किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है।

ई20 पेट्रोल के मुद्दे पर दिल्ली नगर निगम सदन में हंगामा

लगातार शोर-शराबे और नारेबाजी के चलते महापौर प्रवेश वाही ने कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी।

नई दिल्ली,एजेंसी।

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की गुरुवार को आयोजित सदन की बैठक ई20 पेट्रोल के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक के कारण हंगामे की भेंट चढ़ गई। लगातार शोर-शराबे और नारेबाजी के चलते महापौर प्रवेश वाही को सदन की कार्यवाही पहले 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी, लेकिन दोबारा बैठक शुरू होने पर भी स्थिति सामान्य नहीं हुई। इसके बाद महापौर ने कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी।

बैठक शुरू होते ही आम आदमी पार्टी (आप) के पार्षद ई20 पेट्रोल के विरोध में पोस्टर और पंपलेट लेकर सदन में पहुंचे। उन्होंने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि ई20 पेट्रोल से आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा और पुराने वाहनों के संचालन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। विपक्षी पार्षदों ने केंद्र सरकार से इस निर्णय को वापस लेने की मांग की।

दूसरी ओर, भाजपा पार्षदों ने आम आदमी पार्टी के विरोध का जवाब देते हुए नारेबाजी की और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी विरोध दर्ज कराया। हंगामे के दौरान दोनों पक्षों के पार्षदों के बीच तीखी बहस और नोकझोंक देखने को मिली। कार्यवाही स्थगित होने के बाद भी सदन परिसर में राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप जारी रहे। एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने कहा कि देशभर में लोग ई20 पेट्रोल से परेशान हैं और इससे वाहनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ई20 पेट्रोल को लोगों पर थोप रही है और इस निर्णय को वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हाल की बारिश ने दिल्ली नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है तथा राजधानी का शायद ही कोई इलाका ऐसा हो, जहां जलभराव की समस्या न हुई हो।

वहीं, सदन के नेता जय भगवान यादव ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष को दिल्लीवासियों की वास्तविक समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि बैठक में जलजनित बीमारियों और मानसून के दौरान नगर निगम की तैयारियों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी थी, लेकिन विपक्ष ने हंगामा कर कार्यवाही बाधित कर दी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ई20 कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे लोगों को मजबूरी में प्रभावित होना पड़े, क्योंकि उपभोक्ताओं के पास सामान्य पेट्रोल का विकल्प भी उपलब्ध है।

सरकारी विद्यालयों की समस्याओं पर छात्रों के संघर्ष को केवाईएस का समर्थन

नई दिल्ली,एजेंसी।

क्रांतिकारी युवा संगठन (केवाईएस) ने देश के विभिन्न राज्यों में सरकारी विद्यालयों के छात्रों द्वारा बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर किए जा रहे आंदोलनों का समर्थन करते हुए कहा है कि विद्यार्थी शिक्षा से जुड़ी मूलभूत समस्याओं पर प्रशासन को जवाबदेह बना रहे हैं। संगठन ने कहा कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में छात्रों ने पेयजल, शौचालय, पंखे, खेल सुविधाओं, शिक्षकों की नियुक्ति तथा गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन जैसी आवश्यक सुविधाओं की मांग को लेकर प्रदर्शन किए हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में छात्रों के प्रदर्शन के बाद प्रशासन को कुछ समस्याओं का तत्काल समाधान करना पड़ा।

वहीं राजस्थान के जालौर में छात्राओं ने शिक्षकों की कमी के विरोध में विद्यालय पर ताला लगाकर नियुक्ति की मांग की। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के तामिया में छात्रों ने खराब भोजन पर विद्यालय प्रशासन के विरुद्ध कार्रवाई की मांग उठाई। केवाईएस ने कहा कि ये घटनाएं दर्शाती हैं कि विद्यार्थियों का असंतोष केवल परीक्षा संबंधी मुद्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की कमी भी एक गंभीर चुनौती है। संगठन का कहना है कि छात्रों के ये संघर्ष शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार और सभी के लिए समान शैक्षिक अवसर सुनिश्चित करने की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। संगठन ने मुख्यधारा के समाचार माध्यमों से भी इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की अपील की, ताकि सरकारी विद्यालयों की वास्तविक समस्याओं पर व्यापक जनचर्चा हो सके।

महिलाओं के साथ विश्वासघात है लक्ष्मी योजना का मौजूदा स्वरूप: कांग्रेस

नई दिल्ली,एजेंसी।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन योजना में कड़ी शर्तें लगाकर बड़ी संख्या में महिलाओं को इसके दायरे से बाहर कर दिया गया है। यादव ने कहा कि सरकार बनने के डेढ़ वर्ष बाद भी योजना को लागू करने में देरी हुई और अब इसके क्रियान्वयन को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है। दिल्ली में महिलाओं की आबादी लगभग 1.06 करोड़ है, जबकि सरकार केवल 17 लाख महिलाओं को योजना का लाभ देने की बात कर रही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि 10 वर्ष के स्थायी निवास, तीन से अधिक बच्चों वाली महिलाओं को अपात्र घोषित करने, 2.5 लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाओं को बाहर रखने और 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को लाभ से वंचित करने जैसी शर्तें गरीब एवं जरूरतमंद महिलाओं के साथ अन्याय हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने बजट में योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, फिर भी पात्रता की शर्तें इतनी कठोर रखी गयी हैं कि अधिकांश महिलाएं लाभ से वंचित रह जायेंगी।

उन्होंने दावा किया कि लाभार्थियों को तत्काल केवल 1000 रुपये नकद मिलेंगे, जबकि शेष राशि सावधि जमा (एफडी) के रूप में होगी, जिसे तीन वर्ष बाद ही निकाला जा सकेगा। उनके अनुसार बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के दौर में महिलाओं को तत्काल आर्थिक सहायता की आवश्यकता है।

यमुना की सफाई पर हुए खर्च को लेकर श्वेत पत्र जारी करे सरकार: डॉ. नरेश कुमार

नई दिल्ली,एजेंसी।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ. नरेश कुमार ने यमुना की सफाई के लिए 4500 करोड़ रुपये की नयी योजना पर सवाल उठाते हुए प्रदेश सरकार से यमुना सफाई पर अब तक हुए खर्च और उसके वास्तविक परिणामों को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। डॉ. नरेश कुमार ने गुरुवार को संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना की सफाई पर 1500 करोड़ रुपये खर्च करने का दावा किया था और जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह 4500 करोड़ की नयी योजना लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ यमुना में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और दूसरी ओर सरकार बड़े-बड़े दावे कर रही है।

उन्होंने कहा कि श्री प्रवेश साहिब सिंह ने घोषणा की है कि दिल्ली जल बोर्ड की 4500 करोड़ रुपये की योजना के तहत यमुना में बिना उपचार किए गये पानी को गिरने से रोका जाएगा, 15 नए डीएसटीपी लगाए जाएंगे, 37 मौजूदा एसटीपी का आधुनिकीकरण किया जाएगा और 700 कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि दिल्ली के 37 एसटीपी आज भी 100 प्रतिशत क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं।

वर्ष 2011 की एक रिपोर्ट में कम से कम 40 डीएसटीपी की आवश्यकता बताई गयी थी, लेकिन आज भी उस लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सका है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के 20 औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाला प्रदूषित पानी सीधे यमुना में पहुंच रहा है, जिससे नदी में ऑक्सीजन का स्तर लगातार घट रहा है। ऐसे में इन औद्योगिक क्षेत्रों के लिए आईटीपी (औद्योगिक उपचार संयंत्र) लगाए जाने चाहिए, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है।

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सरकार 1600 करोड़ रुपये खर्च कर केवल 244 कॉलोनियों और 54 गांवों को सीवर नेटवर्क से जोड़ने की बात कर रही है, जबकि दिल्ली में 1700 से अधिक कॉलोनियां और 357 गांव हैं। बाकी कॉलोनियों और गांवों के लिए सरकार की क्या योजना है, इस पर सरकार पूरी तरह मौन है।

पश्चिम विहार के चार पार्कों में 976 पेड़ मिले

नई दिल्ली,एजेंसी।

पश्चिम विहार के चार पार्कों में एमसीडी की ओर से किए गए पौधरोपण कार्य का वन विभाग ने निरीक्षण किया। जांच रिपोर्ट के अनुसार, एनएचपी पार्क, दशहरा पार्क, केएल शर्मा पार्क और दुर्गा मंदिर पार्क में कुल 976 पेड़ पाए गए। उत्तर वन प्रभाग के निर्देश पर एमसीडी केशवपुरम बागवानी विभाग की ओर से लगाए गए 1063 पेड़ों की जांच में वन रक्षक सचिन ने एमसीडी सुपरवाइजर के साथ निरीक्षण किया। रिपोर्ट के अनुसार, दशहरा पार्क में 104 (60 प्रतिशत छह फीट से कम), एनएचपी पार्क में 493 (80 प्रतिशत छह फीट से कम), केएल शर्मा पार्क में 345 (40 प्रतिशत छह फीट से कम) और दुर्गा मंदिर पार्क में 32 पेड़ मिले। रिपोर्ट में पेड़ों की सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड लगाने और पहचान के लिए नंबरिंग या टैगिंग करने की सलाह दी गई है।

छात्राओं को मिलेगी 'विद्या वाहिनी' की सौगात

नई दिल्ली,एजेंसी।

दिल्ली सरकार छात्राओं की शिक्षा को सुलभ और सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 31 जुलाई को पूर्व विनोद नगर स्थित खेल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में कक्षा 9 की छात्राओं को 'विद्या वाहिनी' साइकिलों का वितरण करेंगी। कार्यक्रम के प्रथम चरण में 3,000 छात्राओं को साइकिलें प्रदान की जाएंगी। इसके बाद अगले एक माह के भीतर दिल्ली की 1.40 लाख छात्राओं को चरणबद्ध ढंग से 'विद्या वाहिनी' साइकिलें उपलब्ध कराई जाएंगी। इस पहल का उद्देश्य छात्राओं की विद्यालय तक पहुंच आसान बनाना, उनकी नियमित उपस्थिति बढ़ाना तथा उन्हें आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाना है।रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का संकल्प है कि कोई भी बेटी दूरी, संसाधनों की कमी या परिवहन संबंधी कठिनाइयों के कारण शिक्षा से वंचित न रहे।

बायो-गैस प्लांट्स की स्थापना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हुए

नई दिल्ली,एजेंसी।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में गुरुवार को दिल्ली सचिवालय में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और ऑयल इंडिया लिमिटेड के बीच तेहखंड और ओखला में 800 टीपीडी क्षमता वाले कंप्रेस्ड बायो-गैस प्लांट्स की स्थापना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि इन प्लांट्स में अलग किए गए जैविक कचरे से बायो-गैस बनाई जाएगी। इससे दिल्ली में मौजूद कचरे के पहाड़ कम होंगे, स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन बढ़ेगा और हमारा 'स्वच्छ दिल्ली' का संकल्प और मजबूत होगा।

महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत तेखंड एवं ओखला में अत्याधुनिक सीबीजी प्लांट स्थापित किए जाएंगे, जहां प्रतिदिन लगभग 800 टन गीले कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण कर स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा।

यह पहल लैंडफिल पर निर्भरता कम करने, प्रदूषण में कमी लाने तथा दिल्ली में आधुनिक एवं प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने कहा कि यह साझेदारी स्वच्छ, हरित एवं पर्यावरण-अनुकूल दिल्ली के निर्माण के संकल्प को नई गति प्रदान करेगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर और टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

25 लाख रुपये से अधिक बकाया पानी बिल वाले व्यावसायिक परिसरों पर होगी कार्रवाई

नई दिल्ली,एजेंसी।

दिल्ली जल बोर्ड ने लंबे समय से लंबित पानी के बिलों की वसूली के लिए सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जल मंत्री परवेश साहिब सिंह ने गुरुवार को कहा कि जिन व्यावसायिक संपत्तियों पर 25 लाख रुपये या उससे अधिक का पानी बिल बकाया है, उन्हें नोटिस जारी किए जा रहे हैं। सरकार ने ऐसे बकायेदारों को 15 अगस्त 2026 तक बिल जमा करने का अवसर दिया है। निर्धारित समय सीमा तक भुगतान नहीं होने पर नियमों के अनुसार संपत्तियों को अटैच (कुर्क) और सील करने की कार्रवाई की जा सकती है।

परवेश साहिब सिंह ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड के पास पानी का बिल नहीं जमा कराने वालों की संपत्तियों को कुर्क और सील करने का अधिकार है। अब तक ऐसे 1,025 व्यावसायिक परिसरों की पहचान की गई है, जिन पर 25 लाख रुपये या उससे अधिक का जल बिल वर्षों से लंबित है। यदि निर्धारित समय तक उन्होंने भुगतान नहीं किया गया, तो नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने पिछले वर्ष घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लेट पेमेंट सरचार्ज माफी योजना शुरू की थी, जिसे बाद में व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए भी लागू किया गया है।

मंत्री ने कहा कि व्यावसायिक उपभोक्ता भी एलपीएससी योजना का लाभ लेकर अपने लेट पेमेंट सरचार्ज में छूट प्राप्त कर सकते हैं। सरकार को उम्मीद है कि वर्षों से लंबित जल बिलों की वसूली से दिल्ली जल बोर्ड के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य जल बोर्ड के 5,000 करोड़ रुपये के बकाया मूल बिल की वसूली करना है।

इसके लिए लगभग 11,000 करोड़ रुपये के लेट पेमेंट सरचार्ज में छूट दी जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 15 अगस्त को एलपीएससी योजना की समय सीमा समाप्त होने के बाद जो उपभोक्ता बकाया राशि जमा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

युवा कांग्रेस का प्रदर्शन, गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग

नई दिल्ली,एजेंसी।

भारतीय युवा कांग्रेस ने गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब के नेतृत्व में केरल हाउस से जंतर-मंतर तक विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शन के दौरान उदय भानु चिब ने कहा कि छात्रों पर कथित बल प्रयोग के मामले में जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि छात्रों पर पैलेट गन और घातक बल का इस्तेमाल गृह मंत्री के निर्देश पर हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए, और यदि उनकी जानकारी के बिना ऐसा हुआ है तो यह देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करता है।

चिब ने कहा कि युवा कांग्रेस छात्रों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने लोकसभा में गृह मंत्री की मौजूदगी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें सदन में आकर इस मामले पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान का उल्लेख करते हुए कहा कि छात्रों पर हमला करने वालों को सजा मिलनी चाहिए और न्याय सुनिश्चित होना चाहिए। युवा कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से गृह मंत्री अमित शाह को पद से हटाने, मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र उच्चस्तरीय जांच कराने और नैतिक जिम्मेदारी तय करने की मांग की।

जनहित के मुद्दों से भाग रही आम आदमी पार्टी: प्रवेश वाही

नई दिल्ली,एजेंसी।

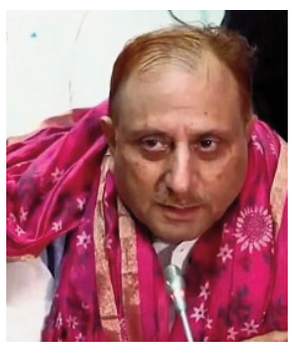

दिल्ली नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक के बाद महापौर प्रवेश वाही ने आम आदमी पार्टी के पार्षदों पर जनहित के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा से बचने और सदन की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मच्छर जनित तथा जल जनित बीमारियों की रोकथाम जैसे गंभीर विषयों पर चर्चा निर्धारित थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने हंगामा कर कार्यवाही को प्रभावित किया। महापौर ने कहा कि विपक्ष का यह रवैया दिल्लीवासियों के हितों के विपरीत है।

प्रवेश वाही ने कहा कि राजधानी में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया तथा जल जनित बीमारियों की रोकथाम को लेकर सदन में विस्तृत चर्चा होनी थी, ताकि जनस्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर प्रभावी रणनीति बनाई जा सके। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने रचनात्मक चर्चा के बजाय राजनीतिक हंगामा कर सदन की कार्यवाही को बाधित किया, जबकि ऐसे विषय सीधे जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े हुए हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी बार-बार ऐसे मुद्दों को सदन में उठाती है, जिनका दिल्ली नगर निगम के कार्यक्षेत्र से कोई संबंध नहीं होता। वहीं नागरिक सुविधाओं और जनहित से जुड़े वास्तविक विषयों पर चर्चा से बचने का प्रयास करती है। महापौर ने कहा कि विपक्ष को जनस्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर सकारात्मक सुझाव देने चाहिए थे, जिससे दिल्लीवासियों को बेहतर लाभ मिल सकता था।

महापौर ने बताया कि दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे व्यापक जनस्वास्थ्य अभियानों और रोकथाम संबंधी उपायों के परिणामस्वरूप इस वर्ष पिछले वर्षों की तुलना में डेंगू के मामलों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी नहीं चाहती थी कि इस उपलब्धि और भविष्य की कार्ययोजना पर सदन में सार्थक चर्चा हो। प्रवेश वाही ने कहा कि विपक्ष के व्यवधान के बावजूद दिल्ली नगर निगम ने नागरिक हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अनेक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए।

उन्होंने बताया कि जनकपुरी क्षेत्र में लंबे समय से बंद पड़े दो कूड़ा ढलावों को हटाने तथा छोटी सब्जी मंडी, जनकपुरी में उपयोग में नहीं आ रहे एक सार्वजनिक शौचालय को हटाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इन निर्णयों से स्थानीय नागरिकों को सुविधा मिलेगी और क्षेत्र की यातायात व्यवस्था भी अधिक सुचारु होगी। कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए महापौर ने नगर निगम आयुक्त को निर्देश जारी किए हैं कि कांवड़ मार्गों और कांवड़ शिविरों के आसपास संचालित सभी अवैध कच्चे एवं पक्के मांस विक्रय केंद्रों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए उनकी यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना नगर निगम की प्राथमिकता है।

महापौर ने राजा पार्क की सड़क का नाम 'श्री दीपक सेठ मार्ग' रखा

नई दिल्ली,एजेंसी।

दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने गुरुवार को वार्ड संख्या-61, राजा पार्क में एक सड़क का नामकरण समाजसेवी स्वर्गीय दीपक सेठ की स्मृति में 'श्री दीपक सेठ मार्ग' के रूप में किया। कार्यक्रम में क्षेत्र के पार्षद अजय रवि हंस भी मौजूद रहें। इस अवसर पर महापौर प्रवेश वाही ने नामकरण पट्टिका का अनावरण किया तथा स्वर्गीय दीपक सेठ को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके सामाजिक योगदान को स्मरण किया। महापौर ने अपने संबोधन में कहा कि स्वर्गीय दीपक सेठ एक प्रसिद्ध समाजसेवी थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज सेवा एवं जनकल्याण के कार्यों के लिए समर्पित किया।

उन्होंने विभिन्न सामाजिक एवं जनहित के कार्यों के माध्यम से समाज के कमजोर एवं जरूरतमंद वर्गों की सेवा की तथा लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का निरंतर प्रयास किया। ऐसे महान व्यक्तित्वों के नाम पर सार्वजनिक स्थलों का नामकरण समाज के प्रति उनके अमूल्य योगदान के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। महापौर ने आशा व्यक्त की कि 'श्री दीपक सेठ मार्ग' आने वाली पीढ़ियों को समाज सेवा, मानवता और जनहित के कार्यों के लिए प्रेरित करता रहेगा। कार्यक्रम के दौरान पार्षद अजय रवि हंस ने भी दीपक सेठ के सामाजिक योगदान को स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने सदैव जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सद्भाव एवं सहयोग की भावना को मजबूत किया।

उन्होंने महापौर एवं दिल्ली नगर निगम का इस सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष अजय खटाना महेश अवाना, डॉ. राजकुमार सेठ सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन उपस्थित नागरिकों द्वारा स्वर्गीय दीपक सेठ के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने एवं उनके आदर्शों का अनुसरण करने के संकल्प के साथ हुआ।

RNI.No DLHIN/25/A2841

स्वामी, प्रकाशक, संपादक देवेंद्र सिंह तोमर एवं मुद्रक रवि भारद्वाज मे. मारुती नंदन प्रिंटर्स एवं पब्लिशर, शक्ति कॉम्प्लेक्स 6/18, समयपुर इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली 110042 से मुद्रित एवं हॉउस नंबर 16/ 9980, गली नंबर-5, सराय रोहिल्ला न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-110005 से प्रकाशित।

संपादकीय कार्यालय - B4/265B केशव पुरम नई दिल्ली -110005। फोन-011-40106508
मोबाइल-9911466900/ 8076353913। Email.saahassamachardainik@gmail.com

संपादक देवेंद्र सिंह तोमर

इस अंक में प्रकाशित खबरों एवं संपादन के लिए पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। किसी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा नई दिल्ली के न्यायालय में होगा।

दिल्ली भाजपा का आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर प्रदर्शन

प्रदर्शन में सांसद योगेन्द्र चांदोलिया, कमलजीत सहरावत, बांसुरी स्वराज, स्वाति मालीवाल, विष्णु मित्तल, सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए।

नई दिल्ली,साहस समाचार।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गुरुवार को प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा के नेतृत्व में कैनिंग लेन स्थित आम आदमी पार्टी (आआपा) कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पंजाब में कथित पेपर लीक मामलों को लेकर पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस की बर्खास्तगी की मांग की। प्रदर्शन के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर मंदिर मार्ग थाने पहुंचाया, जहां करीब एक घंटे बाद चेतावनी देकर छोड़ दिया गया।

प्रदर्शन में सांसद योगेन्द्र चांदोलिया, कमलजीत सहरावत, बांसुरी स्वराज, राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल, प्रदेश महामंत्री विष्णु मित्तल, योगिता सिंह, मोहनलाल गिहारा सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। युवा मोर्चा, ओबीसी मोर्चा और पूर्वांचल मोर्चा के हजारों कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन में भाग लिया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए हर्ष मल्होत्रा ने आम आदमी पार्टी पर केंद्र और पंजाब में अलग-अलग रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र में पेपर लीक के मुद्दे पर नैतिकता की बात करने वाली आआपा पंजाब में हुए कथित पेपर लीक मामलों पर चुप्पी साधे हुए है।

उन्होंने कहा कि पंजाब में टीईटी, 12वीं अंग्रेजी, फार्मेसी ऑफिसर और अन्य भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने के आरोप लगे हैं, लेकिन सरकार जवाबदेही तय नहीं कर रही। मल्होत्रा ने कहा कि केंद्र में इस्तीफा, पंजाब में संरक्षण यही है आआपा का दोहरा चरित्र। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को शिक्षा क्रांति के बजाय पेपर लीक क्रांति बना दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने मांग की है कि पंजाब के शिक्षा मंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाए, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और छात्रों से माफी मांगी जाए।

प्रदेश महामंत्री विष्णु मित्तल ने कहा कि पंजाब में पेपर लीक के मुद्दे पर पहले चुप्पी और फिर इनकार करने की कोशिश से युवाओं में आक्रोश है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे आम आदमी पार्टी का दोहरा रवैया उजागर हुआ है। सांसद योगेन्द्र चांदोलिया ने कहा कि संसद में पेपर लीक पर चर्चा से विपक्ष बचता रहा, जबकि पंजाब के मामलों पर भी आआपा नेतृत्व ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। सांसद कमलजीत सहरावत ने आरोप लगाया कि पिछले चार वर्षों में पंजाब में कई पेपर लीक की घटनाएं सामने आईं, लेकिन राज्य सरकार उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि अपनी गलती स्वीकार किए बिना सुधार संभव नहीं है।

सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि फार्मेसी परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले में भी आम आदमी पार्टी की चुप्पी सवाल खड़े करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए एंटी-पेपर लीक कानून का विपक्ष ने विरोध किया, जबकि पंजाब के मामलों में जवाबदेही से बचा जा रहा है। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने भी पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि पेपर लीक के मुद्दे पर पार्टी पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है और शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लिया जाना चाहिए। भाजपा ने आआपा को चेतावनी दी कि जब तक पंजाब में कथित पेपर लीक मामलों में जवाबदेही तय नहीं होती और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तब तक उसका आंदोलन जारी रहेगा।

एरोसिटी को भविष्य की जरूरतों के मुताबिक विकसित करें: एलजी

नई दिल्ली,साहस समाचार।

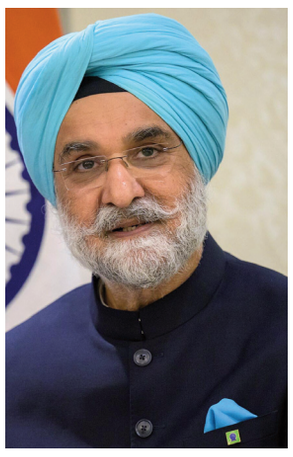

दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने बुधवार को एरोसिटी का दौरा कर यहां चल रहे बुनियादी ढांचा विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि एरोसिटी के विस्तार में केवल आधुनिक इमारतों और व्यावसायिक विकास पर ही नहीं, बल्कि जलभराव से बचाव, जल संरक्षण, हरित अवसंरचना और बेहतर यातायात व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। दौरे के दौरान जीएमआर के अधिकारियों ने एरोसिटी में चल रही परियोजनाओं की जानकारी दी।

उपराज्यपाल ने टिकाऊ शहरी विकास की अवधारणा पर जोर देते हुए कहा कि तेजी से विकसित हो रहे इस क्षेत्र की योजना भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए। उन्होंने मानसून के दौरान जलभराव की समस्या से निपटने के लिए तैयार की जा रही वर्षाजल संरक्षण और बाढ़ प्रबंधन प्रणाली की भी समीक्षा की और इसे मजबूत बनाने के निर्देश दिए। एलजी ने कहा कि एरोसिटी हवाई अड्डे के निकट होने के कारण लगातार व्यावसायिक और आतिथ्य गतिविधियों का केंद्र बन रही है।

ऐसे में यहां बढ़ते यातायात को देखते हुए प्रभावी ट्रैफिक प्रबंधन और मेट्रो की निर्बाध लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना जरूरी है, ताकि यात्रियों और पर्यटकों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिल सके। उन्होंने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और जीएमआर के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया। कहा कि द्वारका और एरोसिटी, दोनों दिल्ली के भविष्य के प्रमुख विकास केंद्र हैं। यदि दोनों क्षेत्रों की आधारभूत संरचना को एकीकृत दृष्टिकोण से विकसित किया जाए तो राजधानी को विश्वस्तरीय शहरी स्वरूप देने में मदद मिलेगी।

उपराज्यपाल ने स्पष्ट किया कि एरोसिटी के भविष्य के विकास में हरित अवसंरचना, पर्यावरण संरक्षण, जल सुरक्षा और टिकाऊ विकास को योजना का मूल आधार बनाया जाए। उनका कहना था कि तेज शहरीकरण पर्यावरण की कीमत पर नहीं होना चाहिए। अधिकारियों के अनुसार, ऐसे निरीक्षणों से परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति का आकलन करने और समय रहते कमियों को दूर करने में मदद मिलती है।

किरण बेदी ने छात्र प्रदर्शनों से निपटने के पुलिस मॉडल पर उठाए सवाल

नई दिल्ली,साहस समाचार।

पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने छात्र विरोध प्रदर्शनों से निपटने के मौजूदा पुलिसिंग मॉडल पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे औपनिवेशिक ब्रिटिश काल की व्यवस्था बताया है। उनका कहना है कि छात्रों के सामने सीधे सशस्त्र बलों की तैनाती उचित नहीं है और इससे व्यवस्था की खामियां उजागर होती हैं। किरण बेदी ने कहा कि किसी भी छात्र प्रदर्शन से निपटने के लिए चरणबद्ध रणनीति अपनाई जानी चाहिए।

उनके अनुसार, सबसे पहले सिविल पुलिस को तैनात किया जाना चाहिए, क्योंकि सिविल पुलिसकर्मी युवाओं से संवाद स्थापित करने में अधिक सक्षम होते हैं और सामान्यतः लाठी लेकर नहीं चलते। यदि किसी सभा को गैरकानूनी घोषित किया जाता है, तब भी शुरुआती स्तर पर सिविल पुलिस की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि स्थिति और अधिक गंभीर हो जाए तथा बैरिकेड तोड़े जाएं, तो दूसरी पंक्ति में महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाना चाहिए।

महिला पुलिसकर्मी हेलमेट और बॉडी आर्मर जैसी सुरक्षा सामग्री से लैस होती हैं, लेकिन वे भी सामान्यतः लाठी का प्रयोग नहीं करतीं। उनका मानना है कि सशस्त्र बलों को केवल तब ही बुलाया जाना चाहिए जब भीड़ पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो जाए और अन्य सभी उपाय विफल हो चुके हों। पूर्व आईपीएस अधिकारी ने सवाल उठाया कि छात्र प्रदर्शनों में सिविल पुलिस की बजाय सीधे सशस्त्र बलों का उपयोग क्यों किया जाता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान व्यवस्था औपनिवेशिक सोच की देन है, जिसका आज भी दुरुपयोग हो रहा है और इसमें सुधार की आवश्यकता है। किरण बेदी ने भीड़ नियंत्रण के दौरान आधुनिक तकनीक के अधिक उपयोग की भी वकालत की।

उन्होंने कहा कि वाटर कैनन का इस्तेमाल अंतिम विकल्प होना चाहिए। साथ ही, घटनास्थल पर कैमरों और ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जानी चाहिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति की गतिविधियों का रिकॉर्ड उपलब्ध रहे और किसी भी घटना की निष्पक्ष जांच संभव हो सके।

एनसीआरटीसी स्टाफ की सतर्कता से बच्चा सकुशल परिजनों से मिला

नई दिल्ली,साहस समाचार।

नमो भारत कॉरिडोर पर एनसीआरटीसी के स्टेशन स्टॉफ ने सतर्कता दिखाते हुए एक बच्चे को सुरक्षित उसके परिजनों से मिलाया। एक संदिग्ध महिला बच्चे को लेकर सराय काले खां नमो भारत स्टेशन पर पहुंची थी। स्टाफ ने संबंधित महिला को दिल्ली पुलिस को सौंपा है। एनसीआरटीसी के अनुसार, स्टेशन स्टाफ ने एक महिला को एक बच्चे के साथ यात्रा करते हुए देखा। बच्चा लगातार रो रहा था और काफी परेशान था। उसकी असहज स्थिति को देखते हुए कर्मचारियों को संदेह हुआ।

पूछताछ में महिला ने बच्चे को अपना बताया, लेकिन बच्चे ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। स्टेशन स्टाफ ने तुरंत मामले की सूचना स्टेशन कंट्रोलर को दी। स्टेशन कंट्रोलर ने तुरंत केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और दिल्ली पुलिस को भी सूचना दी। साथ ही बच्चे के परिजनों से संपर्क किया। आगे की जांच के लिए महिला और बच्चे को दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया।

जिसके बाद बच्चे को सकुशल उसके परिवार से मिलाया गया। एनसीआरटीसी के प्रबंध निदेशक शलभ गोयल ने कहा कि कर्मचारियों की संवेदनशीलता और सतर्कता से एक बड़ी घटना टल गई। नमो भारत परियोजना में यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी स्टेशनों और ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लगातार निगरानी की जाती है।

डीयू में अनुबंध कर्मियों को निकालने की नहीं है कोई योजना: प्रो. योगेश सिंह

नई दिल्ली,साहस समाचार।

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय में अनुबंध आधार पर लगे गैर शिक्षण कर्मचारियों को निकालने की कोई भी योजना विचाराधीन नहीं है। कुलपति ने यह बात दिल्ली विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद (ईसी) की बैठक में इस मामले पर चर्चा के दौरान कही। डीयू ईसी की 1283 वीं बैठक का आयोजन गुरुवार को कुलपति प्रो. योगेश सिंह की अध्यक्षता में हुआ। बैठक में शून्य काल के दौरान ईसी सदस्यों ने अनेक मुद्दों पर गहन चर्चा की।

ज्ञात हो कि डीयू में बड़ी संख्या में अनुबंध पर कर्मचारी काम करते हैं। कार्यकारी परिषद की बैठक में दिल्ली विश्वविद्यालय के कर्मचारियों (कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों सहित) के आश्रितों को सोशल सिक्योरिटी फायदे देने के लिए 'लाइफ इंश्योरेंस स्कीम' की 'ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम' को लागू करने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इसके तहत मास्टर पॉलिसी के ज़रिए 20 लाख रुपये का कवरेज मिलेगा, जिसके लिए हर सब्सक्राइबर को हर महीने 500 रुपये के साथ जीएसटी का प्रीमियम देना होगा। यह कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक स्कीम है।

इस अवसर पर कुलपति ने कहा कि हमारा लक्ष्य अगले 5 वर्षों में दिल्ली विश्वविद्यालय को दुनिया के सर्वोच्च 200 विश्वविद्यालयों में शामिल करना है। बैठक के दौरान अकादमिक परिषद में पारित शैक्षणिक मुद्दों को भी स्वीकृति प्रदान की गई। ईसी बैठक के दौरान वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विश्वविद्यालय, उसके द्वारा संचालित हॉल और हॉस्टल, प्रोविडेंट फंड और राष्ट्रीय पेंशन योजना के वार्षिक खातों पर विचार करना और उन्हें मंज़ूरी दी गई। अंडरग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क (यूजीसीएफ़-2022) के तहत विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के सहयोग से 'सेमेस्टर अवे प्रोग्राम' शुरू करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। वेतन सुरक्षा (पे प्रोटेक्शन) के तहत बनाई गई कमेटी की सिफारिशों को डीयू ईसी ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत उन अलग-अलग कॉलेजों के शिक्षकों के वेतन सुरक्षा के अनुरोध पर विचार किया जाएगा, जिन्हें यूनिवर्सिटी/कॉलेजों में स्थायी तौर पर नियुक्त होने से पहले, सही प्रक्रियाओं और नियमों (जैसे ऑल इंडिया विज्ञापन के जरिए खुली भर्ती और सही तरीके से बनी सिलेक्शन कमेटी) का पालन करते हुए अस्थायी तौर पर नियुक्त किया गया था (चाहे वे उसी कॉलेज/संस्थान में हों या भारत सरकार/एनसीटी दिल्ली से फंड पाने वाले समान संस्थानों में।

राजा गार्डन परिवहन कार्यालय का परिवहन मंत्री ने किया औचक निरीक्षण

नई दिल्ली,साहस समाचार।

दिल्ली सरकार की पारदर्शी, नागरिक-केंद्रित और जवाबदेह प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने गुरुवार को राजा गार्डन स्थित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में 1000 से अधिक लंबित मामले पाए जाने पर उन्होंने अधिकारियों को 10 दिनों के भीतर सभी लंबित प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

साथ ही स्पष्ट चेतावनी दी कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर संतोषजनक प्रगति नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय की कार्यप्रणाली का विस्तृत अवलोकन किया तथा विभिन्न सेवा कक्षों का निरीक्षण कर अधिकारियों और कर्मचारियों से कार्य व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने कार्यालय में उपस्थित नागरिकों से सीधे संवाद कर परिवहन सेवाओं से जुड़े उनके अनुभव और शिकायतों को भी गंभीरता से सुना। मंत्री ने कहा कि जनसुविधाओं में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी अथवा अनियमितता स्वीकार नहीं की जाएगी और सरकार इस विषय में शून्य सहनशीलता की नीति पर कार्य कर रही है।

समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि कार्यालय में 1000 से अधिक आवेदन और प्रकरण विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं। इस पर चिंता व्यक्त करते हुए डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने निर्देश दिए कि सभी लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए तथा 10 दिनों के भीतर विस्तृत अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि निर्धारित अवधि में लंबित मामलों में उल्लेखनीय कमी नहीं आती है तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी।

परिवहन सेवाओं में विलंब को लेकर नागरिकों से प्राप्त शिकायतों की समीक्षा करते हुए मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पात्र आवेदकों को अनावश्यक रूप से बार-बार कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने कहा कि अधिकांश परिवहन सेवाएं पहले से ही ऑनलाइन उपलब्ध हैं, इसलिए केवल उन्हीं मामलों में आवेदकों को कार्यालय बुलाया जाए, जहां अभिलेखों का प्रत्यक्ष सत्यापन अथवा आवेदक की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक हो।

डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने अधिकारियों को सेवा वितरण व्यवस्था को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक आवेदन का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि नागरिकों को बिना किसी असुविधा के गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्राप्त हो सकें। उन्होंने कहा कि राजा गार्डन राजधानी के प्रमुख क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में शामिल है और यहां आने वाले प्रत्येक नागरिक को निर्धारित समय के भीतर पारदर्शी तथा प्रभावी सेवाएं मिलनी चाहिए।

निरीक्षण के दौरान कई नागरिकों ने तकनीकी बाधाओं के कारण परिवहन सेवाओं के प्रभावित होने की शिकायत भी मंत्री के समक्ष रखी। इस पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वाहन चालक अनुज्ञापत्र, वाहन पंजीकरण, स्वामित्व हस्तांतरण तथा परिवहन विभाग से संबंधित सभी आवेदनों का समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही सेवा वितरण में बाधा उत्पन्न कर रही तकनीकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर तत्काल समाधान करने के निर्देश भी दिए।

डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार नागरिकों को पारदर्शी, उत्तरदायी और जनहितकारी प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि राजधानी के प्रत्येक नागरिक को बिना अनावश्यक विलंब और सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाए समय पर सेवाएं प्राप्त हों। उन्होंने कहा कि राजधानी के सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों के कार्यों की नियमित निगरानी की जाएगी और जनसेवा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सभी कदम उठाए जाएंगे।

बात मुद्दे की

आलोक गौड़

आयोग अदालत नहीं, फिर उसकी सिफारिशों का क्या होगा?

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की शक्तियों की सीमा तय कर दी है। आयोग अदालत नहीं है। वह जांच कर सकता है, दस्तावेज मांग सकता है, गवाही और साक्ष्य ले सकता है, किसी शिकायत पर अपनी राय बना सकता है, सरकार को सलाह दे सकता है और सिफारिश कर सकता है, लेकिन अदालत की तरह किसी पक्ष के अधिकारों पर बाध्यकारी फैसला नहीं सुना सकता।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून की दृष्टि से स्पष्ट है। लेकिन लोकतंत्र की दृष्टि से इसके बाद एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर आयोग अदालत नहीं है तो सरकार क्या है?

क्या सरकार आयोग की सिफारिश को भी सिर्फ एक कागज मानकर रख सकती है? यही इस फैसले का असली मुद्दा है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कोई सामान्य सरकारी समिति नहीं है। यह संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत बना संवैधानिक निकाय है। उसे अनुसूचित जातियों के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा से जुड़े मामलों की जांच करने और राष्ट्रपति को रिपोर्ट देने का दायित्व सौंपा गया है। यानी संविधान ने उसे सिर्फ सजावटी संस्था बनाकर नहीं रखा है।

लेकिन संविधान ने यह भी नहीं कहा कि आयोग अदालत की तरह दो पक्षों के बीच विवाद का अंतिम फैसला कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने इसी सीमा को स्पष्ट किया है।

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि आयोग की भूमिका सलाह और सिफारिश देने की है, न्यायिक निर्णय देने की नहीं। उसके पास जांच के लिए सिविल कोर्ट जैसी कुछ प्रक्रियात्मक शक्तियां हो सकती हैं, लेकिन इससे वह अदालत या ट्रिब्यूनल नहीं बन जाता। यह फर्क समझना जरूरी है।

जांच करने की शक्ति और फैसला सुनाने की शक्ति एक चीज नहीं है। आयोग किसी पीड़ित की शिकायत सुन सकता है। संबंधित विभाग से रिकॉर्ड मांग सकता है। अधिकारियों को बुला सकता है। तथ्यों की पड़ताल कर सकता है। यह देख सकता है कि अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हुआ या नहीं। लेकिन अंत में वह यह आदेश नहीं दे सकता कि अमुक व्यक्ति को नौकरी वापस दी जाए, अमुक अधिकारी को दंडित किया जाए या किसी पक्ष का अधिकार अंतिम रूप से तय हो गया।

यह काम अदालत का है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी वजह से आयोग की उस दलील को भी स्वीकार नहीं किया कि उसके अधिकारों में "सुरक्षा" शब्द शामिल है, इसलिए उसे कानून लागू कराने की शक्ति भी मिल जाती है। अदालत ने कहा कि ऐसा अर्थ निकालना आयोग को वह न्यायिक शक्ति देना होगा जो संविधान ने उसे दी ही नहीं है। यहां तक तो मामला साफ है। लेकिन अब सवाल सरकार का है।

मान लीजिए आयोग किसी मामले की महीनों जांच करता है। पीड़ित की शिकायत सही पाता है। दस्तावेज जुटाता है। संबंधित विभाग से जवाब मांगता है और अंततः सरकार को सिफारिश करता है कि पीड़ित के साथ न्याय किया जाए।

सरकार कह दे कि "सिफारिश थी, हमने नहीं मानी।" क्या मामला खत्म?

नहीं। यहीं लोकतांत्रिक जवाबदेही शुरू होती है।

अगर आयोग की सिफारिश अदालत का आदेश नहीं है तो उसका अर्थ यह भी नहीं हो सकता कि सरकार उसे पढ़े बिना कूड़ेदान में डाल दे। संवैधानिक संस्था की सिफारिश को न मानने का अधिकार सरकार के पास हो सकता है, लेकिन उससे यह सवाल खत्म नहीं होता कि क्यों नहीं मानी?

सरकार को कारण बताना चाहिए। क्योंकि आयोग की शक्ति को न्यायिक शक्ति नहीं बनाने का अर्थ यह नहीं कि सरकार की जवाबदेही खत्म हो गई। बल्कि उल्टा है कि जितनी बाध्यकारी शक्ति आयोग के पास नहीं है, उतनी ही अधिक पारदर्शिता सरकार के पास होनी चाहिए।

यही बात अनुसूचित जातियों के अधिकारों से आगे भी जाती है। देश में अलग-अलग वर्गों और समुदायों के अधिकारों की निगरानी के लिए संवैधानिक और वैधानिक आयोग बने हुए हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जैसे निकाय अलग-अलग कानूनों और संवैधानिक प्रावधानों के तहत काम करते हैं। इस फैसले का असर इन संस्थाओं की शक्तियों की व्याख्या पर भी बहस को प्रभावित कर सकता है, हालांकि हर आयोग की कानूनी संरचना और अधिकार अलग-अलग हैं। और यही वह जगह है जहां हमें आयोगों की उपयोगिता पर गंभीर बहस करनी चाहिए।

अगर किसी आयोग को पीड़ित की शिकायत पर जांच का अधिकार दिया गया है, लेकिन उसके निष्कर्ष को लागू कराने की शक्ति नहीं है तो फिर उसकी सिफारिशों का क्या होगा? अगर सरकारें उन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं हैं तो क्या हर सिफारिश के साथ सरकार को लिखित कारण बताना अनिवार्य नहीं होना चाहिए? अगर आयोग की रिपोर्ट संसद या राष्ट्रपति के सामने रखी जाती है तो क्या संसद को यह नहीं पूछना चाहिए कि सरकार ने आयोग की कितनी सिफारिशें मानीं और कितनी खारिज कीं? और सबसे महत्वपूर्ण कि अगर सरकार ने सिफारिश नहीं मानी तो उसने क्यों नहीं मानी? यही असली मुद्दे की बात है।

क्योंकि संविधान ने आयोगों को इसलिए नहीं बनाया कि वे पीड़ितों को एक और दरवाजा दिखाकर वापस भेज दें। आयोगों का मकसद उन लोगों की आवाज को संस्थागत ताकत देना है जिनकी आवाज अक्सर सत्ता और प्रशासन के गलियारों में दब जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने आयोगों को अदालत बनने से रोक दिया है। ठीक है। लेकिन अब संसद और सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि आयोग बेअसर संस्था न बन जाएं।

यह फर्क बहुत महत्वपूर्ण है। अदालत का विकल्प आयोग नहीं है। लेकिन आयोग भी महज सिफारिशों का डाकघर नहीं हो सकता। उसके पास जांच की शक्ति है तो उसकी जांच गंभीर होनी चाहिए। उसे रिपोर्ट देने का अधिकार है तो रिपोर्ट सार्वजनिक महत्व की होनी चाहिए। उसे सरकार को सिफारिश देने का अधिकार है तो सरकार को उस सिफारिश पर जवाबदेह होना चाहिए।

वरना गरीब, दलित, आदिवासी, महिला, अल्पसंख्यक या किसी भी कमजोर वर्ग का वह नागरिक, जो न्याय की उम्मीद में आयोग के पास पहुंचता है, आखिर जाएगा कहां? अदालत में जाने की अपनी लागत है। मुकदमे वर्षों चलते हैं। आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए न्याय तक पहुंच आसान नहीं है। ऐसे में संवैधानिक आयोगों की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन आयोग अगर आदेश नहीं दे सकता तो सरकार के पास एक बड़ा नैतिक और लोकतांत्रिक दायित्व है। सिफारिश को मानिए या ठुकराइए l लेकिन जवाब दीजिए। यही वह बिंदु है जिस पर संसद को कानून और प्रक्रिया को और मजबूत करना चाहिए।

हर संवैधानिक आयोग की सिफारिश पर सरकार की समयबद्ध प्रतिक्रिया हो। स्वीकार की तो क्या कार्रवाई हुई, बताइए। अस्वीकार की तो कारण बताइए। लंबित है तो कब तक निर्णय होगा, बताइए। ताकि आयोग की रिपोर्ट अलमारी में बंद होकर धूल न खाती रहे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आयोग की सीमा तय की है। अब लोकतंत्र की बारी है कि वह आयोग की प्रासंगिकता और सरकार की जवाबदेही की सीमा तय करे। क्योंकि न्याय सिर्फ अदालत के आदेश का नाम नहीं है। न्याय का पहला कदम है कि किसी पीड़ित की बात सुनी जाए। दूसरा कदम है यह है कि उसकी शिकायत की निष्पक्ष जांच हो। तीसरा कदम है कि जिम्मेदार संस्था अपनी बात सरकार के सामने रखे। और चौथा कदम है कि सरकार बताए कि उसने क्या किया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आयोग अदालत नहीं है।

संपादकीय

सिर्फ मौसम नहीं बदल रहा, दिल्ली का भविष्य बदल रहा है

दिल्ली को देश की राजधानी कहा जाता है। यहां संसद है, सरकार है, बड़े-बड़े संस्थान हैं, आधुनिक इमारतें हैं और विकास की चमक भी दिखाई देती है। लेकिन इसी चमक के पीछे एक ऐसा संकट तेजी से आकार ले रहा है, जिस पर अब केवल चर्चा नहीं, बल्कि गंभीर और स्थायी कार्रवाई की जरूरत है। यह संकट है बदलता मौसम और बढ़ता शहरी तापमान। आज मौसम का बदलना केवल प्रकृति का विषय नहीं रह गया है। यह स्वास्थ्य, पानी, बिजली, रोजगार, यातायात, निर्माण और शहर की अर्थव्यवस्था से सीधे जुड़ा सवाल बन चुका है। दिल्ली में गर्मी से निपटने के लिए गर्मी कार्ययोजना जैसे उपाय किए जा रहे हैं और प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां भी होती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम हर साल गर्मी आने के बाद तैयारी करने के बजाय शहर की योजना ही ऐसी बना सकते हैं कि गर्मी का असर कम हो? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शहर केवल तापमान से गर्म नहीं होता। कंक्रीट की बढ़ती सतह, पेड़ों की कमी, खुले स्थानों का सिकुड़ना, वाहनों की बढ़ती संख्या, निर्माण गतिविधियां और प्राकृतिक जल स्रोतों की उपेक्षा मिलकर शहरी गर्मी को और बढ़ाते हैं। किसी इलाके में पेड़ कम हों, पैदल मार्ग और सड़कें पूरी तरह कंक्रीट से ढकी हों तथा आसपास खुली जमीन या जलाशय न हों तो वहां रहने वाले लोगों को वही तापमान दूसरे हरे-भरे इलाके की तुलना में कहीं अधिक कठोर महसूस हो सकता है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि इस संकट का असर सभी पर समान नहीं पड़ता। वातानुकूलित कमरों में रहने वाला व्यक्ति कुछ समय के लिए गर्मी से बच सकता है, लेकिन सड़क किनारे काम करने वाला मजदूर, रिक्शा चालक, सामान पहुंचाने वाला कर्मचारी, सुरक्षा गार्ड, रेहड़ी-पटरी वाला या खुले में काम करने वाला व्यक्ति मौसम की मार से बच नहीं सकता। गर्मी उसके लिए केवल असुविधा नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और रोजी-रोटी दोनों का सवाल बन जाती है।

यही कारण है कि जलवायु नीति को केवल पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी मानना भूल होगी। सड़क बनाने वाला विभाग, नगर निकाय, जल विभाग, बिजली विभाग, परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग और शहरी नियोजन से जुड़े संस्थान सभी को एक साझा रणनीति के तहत काम करना होगा। दिल्ली की आधिकारिक जलवायु नीति भी जल संसाधन, स्वास्थ्य, ऊर्जा, परिवहन, शहरी नियोजन और हरित क्षेत्र जैसे कई क्षेत्रों को जलवायु परिवर्तन से जोड़ती है।

दिल्ली के सामने दूसरा बड़ा प्रश्न पानी का है। गर्मी बढ़ेगी तो पानी की मांग बढ़ेगी। दूसरी ओर अनियोजित निर्माण और प्राकृतिक जल स्रोतों के कमजोर होने से पानी का संकट और गहरा सकता है। दिल्ली जल बोर्ड ने वर्ष 2026 के लिए विधानसभा क्षेत्रवार ग्रीष्मकालीन कार्ययोजना भी जारी की है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि पानी का संकट केवल टैंकरों और आपातकालीन आपूर्ति से हल नहीं होगा। वर्षा जल संचयन, जलाशयों का संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और पानी के विवेकपूर्ण इस्तेमाल को शहर की रोजमर्रा की व्यवस्था का हिस्सा बनाना होगा।

इसी तरह पेड़ लगाना भी केवल फोटो खिंचवाने वाला अभियान नहीं होना चाहिए। पौधे लगाना आसान है, लेकिन उन्हें बड़ा करना असली चुनौती है। दिल्ली को अब संख्या से अधिक गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा। किस क्षेत्र में कितनी हरियाली चाहिए, कौन-से पेड़ स्थानीय मौसम के अनुकूल हैं, पौधों की देखभाल कौन करेगा और पांच साल बाद उनकी स्थिति क्या होगी इन सवालों के जवाब भी सार्वजनिक होने चाहिए। शहरी नियोजन में भी बड़ा बदलाव आवश्यक है। दिल्ली की गर्मी कार्ययोजना में लंबे समय के लिए सड़कों के पुनर्निर्माण, वृक्षारोपण, पार्क, हरित गलियारे, जलाशयों और अत्यधिक गर्म इलाकों की सतहों में बदलाव जैसे उपायों पर जोर दिया गया है। इसका अर्थ साफ है गर्मी का समाधान केवल वातानुकूलक, पंखे और पानी के छिड़काव में नहीं है। शहर की संरचना बदलनी होगी। हमें यह भी तय करना होगा कि विकास का अर्थ आखिर है क्या? क्या हर खाली जमीन पर निर्माण कर देना विकास है? क्या हर सड़क को कंक्रीट से ढक देना विकास है? क्या पेड़ काटकर उसके बदले कुछ पौधे लगा देना पर्याप्त है? अगर विकास इंसान को ही असुरक्षित बना दे तो उस विकास की दिशा पर सवाल उठाना जरूरी है।

डिजिटल संप्रभुता में सीधा हस्तक्षेप

डॉ. आशीष वशिष्ठ

सोशल मीडिया ने आम आदमी को बहुत बड़ी ताकत दी है। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म के जरिए लोग बिना किसी रोक-टोक अपनी बात तुरंत लाखों लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से संगठित रूप से निगेटिव चीजों को प्रचारित करने का प्रयास हो रहा है। सोशल मीडिया ने कई देशों में सरकारों के खिलाफ जन-आंदोलनों को संगठित करने में अहम भूमिका निभाई है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नीट पेपर लीक को लेकर जेन-जी को संबोधित करते हुए जो पहला सेल्फी वीडियो अपलोड किया था, उसे मेटा ने हटा दिया था। यही वीडियो इंस्टाग्राम पर 24 घंटे के भीतर 300 मिलियन से अधिक बार देखा गया था। बाद में जब इस पर हंगामा हुआ, तब कंपनी ने सफाई देते हुए कहा कि वीडियो को जानबूझकर नहीं हटाया गया बल्कि यह एक तकनीकी खामी थी। इतनी बड़ी कंपनी का तकनीकी खामी का तर्क आसानी से गले नहीं उतरता। समर्थकों का आरोप है कि यह एक सोची-समझी साजिश है ताकि सरकार की बात करोड़ों युवाओं तक पहुंचने से रोका जा सके। फिलहाल यह मामला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की नीतियों, कंटेंट मॉडरेशन और डिजिटल जवाबदेही को लेकर नई बहस का विषय बन गया है।

वास्तव में, मेटा द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो सेंसर करना भारतीय लोकतंत्र और डिजिटल संप्रभुता में सीधा हस्तक्षेप है। यह कोई सामान्य कंटेंट मॉडरेशन नहीं है बल्कि एक विदेशी प्लेटफॉर्म द्वारा यह तय करने की तानाशाही कोशिश है कि भारतीय नागरिक क्या देख सकते हैं। अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनियां दुनियाभर में नैरेटिव तय करके सरकारें बदलने का खेल खेलती रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी की पोस्ट पर रोक लगाना इस बात का प्रमाण है कि उपभोक्ता जो देख रहे हैं, वह कंपनियां तय करती हैं।

सोशल मीडिया ने आम आदमी को बहुत बड़ी ताकत दी है। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म के जरिए लोग बिना किसी रोक-टोक अपनी बात तुरंत लाखों लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से संगठित रूप से निगेटिव चीज़ों को प्रचारित करने का प्रयास हो रहा है। सोशल मीडिया ने कई देशों में सरकारों के खिलाफ जन-आंदोलनों को संगठित करने में अहम भूमिका निभाई है। अरब क्रांति, श्रीलंका और बांग्लादेश के हालिया उदाहरण इसके बड़े प्रमाण हैं, जहां डिजिटल प्लेटफॉर्म ने जनता को एकजुट किया। पिछले एक दशक में देश में विपक्ष और विभिन्न संगठनों द्वारा जितने भी आंदोलन हुए हैं, उनमें निगेटिव, फर्जी और भड़काऊ सामग्री प्रचारित-प्रसारित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म का जमकर प्रयोग हुआ। हालिया कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में सोशल मीडिया ने बड़ी भूमिका निभाई। सोशल मीडिया पर बनी एक पार्टी के रातोंरात करोड़ों फॉलोअर बन गए। इसके आंदोलन के दौरान सुनियोजित सोशल मीडिया कैंपेन चलाए गए। जनता के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए सीजेपी ने उस वामपंथी सोशल मीडिया तंत्र की शरण ली है जो लंबे समय से राष्ट्रवादी आवाजों को दबाने के मिशन में जुटा है।

भारत में सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता को बिगाड़ने के प्रयास पिछले एक दशक से जारी हैं। फेक न्यूज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनित डीपफेक और सीमा पार से संचालित होने वाले फर्जी अकाउंट्स के जरिए सुनियोजित ढंग से भ्रम और तनाव पैदा किया जा रहा है। सीएए विरोध प्रदर्शन और किसान आंदोलन दोनों ही प्रमुख घटनाओं के दौरान सोशल मीडिया के दुरुपयोग के कई गंभीर मामले सामने आए थे। इन आंदोलनों के दौरान डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल न केवल सूचना साझा करने के लिए हुआ बल्कि इसके जरिए भारी मात्रा में भ्रामक जानकारियां, अफवाह और नफरत फैलाने वाले कंटेंट प्रसारित किए गए। ये खुला तथ्य है कि वामपंथी और लिबरल इकोसिस्टम ने इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर राष्ट्रवादी आवाजों को दबाने और अपनी सहूलियत का नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया, जिसके जवाब में भारत सरकार ने समय-समय पर राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के तहत कड़े कदम उठाए।

सोशल मीडिया ख़ासकर इंस्टाग्राम पर कॉक्रोच जनता पार्टी के प्रदर्शन और सोनम वांगचुक को उसके समर्थन के लिए जो ज्वार अचानक उठा था, अब उस विद्रूप और उच्छृंखल सुनामी लहरों का थमना शुरू हो गया है। इंस्टाग्राम पर उनके लिए समर्थन पूरी तरह से फर्जी और प्रायोजित था। इसके लिए तीन प्रोफ़ेशनल एजेंसियों ने पैसे देकर वृहद स्तर पर प्रचार अभियान चलाया। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु की तीन एजेंसियों ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देकर पूरा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। भारत को श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की तरह जलाने की पूरी तैयारी थी।

प्रदर्शन जारी रखने के लिए विभिन्न देशों से खाने-पीने और अन्य आर्थिक मदद दी जा रही थी। इस सुनियोजित षडयंत्र से जुड़ी तमाम रपट और जानकारियां पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं। चूंकि इस षड्यंत्र का जाल सामने आ गया है, जिसका सार्वजनिक पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। यह खेल आगे न हो इसलिए सरकार और प्रशासन को चाहिए कि इन मामलों की गहराई से जांच करे और यह पता लगाये कि आख़िर कौन-सी ताकतें इस अभियान में मोटी फंडिंग कर भारत में माहौल खराब करने की कोशिश कर रही हैं?

चीन में फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पूरी तरह ब्लॉक हैं। उत्तर कोरिया में सोशल मीडिया पर पूरी तरह बैन है। आमलोग सिर्फ क्वांगमयोंग नाम के सरकारी इंट्रानेट तक सीमित रहते हैं। ईरान में फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब ब्लॉक हैं। ब्राजील ने एक्स को अस्थायी तौर पर बैन किया है। मिस्र, सऊदी अरब और सीरिया जैसे कई देशों में राजनीतिक कारणों से सोशल मीडिया पर कड़ी पाबंदियां हैं। इसके पीछे की वजह सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करना, फेक न्यूज को रोकना है।

असल में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जुड़ाव-संचालित एल्गोरिदम को प्राथमिकता देते हैं, तथ्यात्मक जानकारी की तुलना में सनसनीखेज और भ्रामक सामग्री को बढ़ाते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि फर्जी खबरें सच्ची खबरों की तुलना में छह गुना तेज़ी से फैलती हैं। सोशल मीडिया उपयोगकर्त्ता अक्सर ऐसी सामग्री से जुड़ते हैं जो उनकी पूर्व-मौजूदा मान्यताओं के अनुरूप होती है, जिससे गलत सूचना को बल मिलता है।

प्रधानमंत्री मोदी हर आयुवर्ग खासकर युवाओं में बेहद लोकप्रिय हैं। युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता और सीधे कनेक्ट करने की शैली अक्सर विपक्षी दलों को खटकती है। लोकप्रियता के प्रमाण के तौर पर सीजेपी प्रदर्शन के दौरान इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी ने दो वीडियो पोस्ट किए थे, जिन पर करोड़ों में लाइक हैं, पीएम मोदी के इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की संख्या 10.5 करोड़ के पार हो चुकी है। सीजेपी आंदोलन में सिर्फ एक सप्ताह के दौरान उनके एकाउंट में नए 40 लाख फॉलोअर्स जुड़े हैं। पेपर लीक जैसी गंभीर समस्या पर कड़ा रुख अपनाते हुए मोदी सरकार ने हाई पावर टास्क फोर्स और फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। वहीं, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिये पेपर लीक रोधी कानून में आवश्यक बदलाव कर उसे संसद से पास कराया है। ये गंभीर चिंता का विषय है कि अगर मेटा विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार कर सकती है तो क्या उन्होंने एक विशेष इंस्टा पोस्ट को वायरल नहीं किया होगा? क्या आप दावे से कह सकते हैं कि ये नहीं हुआ होगा? सोशल मीडिया का सारा नियंत्रण अमेरिकी कंपनियों के पास है। ये उनके लिए चुटकी बजाने जितना आसान काम है। भारतीय विज्ञापन राजस्व से अरबों कमाने वाले ये अमेरिकी प्लेटफॉर्म्स अब भारतीय लोकतंत्र को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं, जिन पर मोदी सरकार को तुरंत सख्त 'रेड लाइन्स' तय करनी चाहिए। सीजेपी आंदोलन के दौरान 20 जुलाई को हुई हिंसा में अल्गोरिदम का भी बहुत बड़ा खेल है। इन विदेशी कंपनियों की मंशा साफ है। सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

बढ़ती गर्मी और मानव जीवन पर मंडराता खतरा

सुनील कुमार महला

आज धरती का तापमान लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। वास्तव में, कहना ग़लत नहीं होगा कि वैश्विक तापमान में लगातार हो रही वृद्धि आज पूरी मानवता के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुकी है। जीवाश्म ईंधनों के अत्यधिक उपयोग, वनों की अंधाधुंध कटाई, तेज़ी से बढ़ते औद्योगीकरण, शहरीकरण और कार्बन उत्सर्जन के कारण पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है। इसका प्रभाव पूरी दुनिया में हीटवेव, सूखा, बाढ़, अनियमित वर्षा, समुद्र-स्तर में वृद्धि और जंगलों में भीषण आग जैसी घटनाओं के रूप में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बढ़ती गर्मी का सबसे अधिक दुष्प्रभाव बच्चों, बुजुर्गों, श्रमिकों तथा गरीब और विकासशील देशों की आबादी पर पड़ रहा है।

इसी संदर्भ में शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान (इपीआइसी) के अंतर्गत कार्यरत क्लाइमेट इंपेक्ट लैब ने मार्च 2026 में 'अडेप्टेशन रोडमैपः ह्यूमन हेल्थ-बढ़ते तापमान का मौत पर असर मापना ताकि अडेप्टेशन प्लानिंग को टारगेट किया जा सके' शीर्षक से एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रकाशित की है।

यह रिपोर्ट बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण होने वाली ताप-जनित (हीट-रिलेटेड) मौतों तथा उनसे बचाव के उपायों का विस्तृत आकलन प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट के अनुसार यदि वैश्विक तापमान वर्तमान गति से बढ़ता रहा, तो अत्यधिक गर्मी के कारण हर वर्ष लगभग 4.3 लाख (430,000) अतिरिक्त लोगों की मृत्यु हो सकती है। इसका सबसे अधिक प्रभाव गरीब देशों पर पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जलवायु अनुकूलन (एडेप्टेशन) के लिए आवश्यक संसाधन सीमित हैं। रिपोर्ट यह भी स्पष्ट करती है कि मृत्यु दर केवल तापमान बढ़ने पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि लोगों को विश्वसनीय बिजली, एयर कंडीशनर, शीतल आवास, स्वास्थ्य सेवाएँ और प्रभावी हीट-एक्शन प्लान जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं या नहीं। दक्षिण एशिया और उप-सहारा अफ्रीका को सबसे अधिक जोखिम वाला क्षेत्र बताया गया है, क्योंकि वहाँ अत्यधिक गर्मी के साथ गरीबी और ऊर्जा की कमी भी मौजूद है। बढ़ते तापमान का एक और गंभीर परिणाम जंगलों में लगने वाली आग की बढ़ती घटनाएँ हैं। इससे न केवल जैव-विविधता और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुँचता है, बल्कि मानव बस्तियाँ भी खतरे में आ जाती हैं। यूरोप, जिसे कभी अपेक्षाकृत ठंडा क्षेत्र माना जाता था, अब वहाँ भी वनाग्नि की घटनाएँ लगातार बढ़ रही हैं। दक्षिण-पश्चिमी फ्रांस के जंगल हाल के वर्षों में भीषण आग से प्रभावित हुए, जिसके कारण लगभग ढाई लाख लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। भारत में भी हर वर्ष जंगलों की आग से वन संपदा, वन्यजीवों और पर्यावरण को व्यापक क्षति होती है।

आज धरती का तापमान लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। वास्तव में, कहना ग़लत नहीं होगा कि वैश्विक तापमान में लगातार हो रही वृद्धि आज पूरी मानवता के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुकी है। जीवाश्म ईंधनों के अत्यधिक उपयोग, वनों की अंधाधुंध कटाई, तेजी से बढ़ते औद्योगीकरण, शहरीकरण और कार्बन उत्सर्जन के कारण पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है।

रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि यदि अभी से स्वच्छ ऊर्जा, विश्वसनीय बिजली, किफायती शीतलन (कूलिंग) सुविधाओं, प्रभावी हीट-एक्शन प्लान, सुदृढ़ स्वास्थ्य सेवाओं और जलवायु-अनुकूल अवसंरचना में निवेश किया जाए, तो वर्ष 2050 तक होने वाली लाखों संभावित मौतों को रोका जा सकता है। सरल शब्दों में कहें तो यह रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि जलवायु परिवर्तन अब केवल पर्यावरण का विषय नहीं रह गया है, बल्कि यह मानव स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा के लिए भी गंभीर संकट बन चुका है। इसलिए ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, हरित ऊर्जा को बढ़ावा, वनों का संरक्षण और प्रभावी जलवायु अनुकूलन उपाय अपनाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विश्व स्तर पर अनेक योजनाएँ और कार्यक्रम बनाए गए हैं, लेकिन उनका प्रभावी क्रियान्वयन अभी भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। विडंबना यह है कि जिन देशों का कार्बन उत्सर्जन में योगदान सबसे कम है, वही जलवायु परिवर्तन के सबसे गंभीर दुष्प्रभाव झेल रहे हैं। दूसरी ओर, विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, बढ़ता शहरीकरण, औद्योगीकरण, वाहनों की बढ़ती संख्या तथा बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई कार्बन उत्सर्जन को लगातार बढ़ा रहे हैं। इसमें विकसित देशों का योगदान सबसे अधिक है, फिर भी जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों में उनकी अपेक्षित सक्रियता दिखाई नहीं देती।

अंततः निष्कर्ष के तौर पर यहां पर यह कहना ग़लत नहीं होगा कि वैश्विक तापमान को कम करना केवल सरकारों की नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। इसके लिए जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम कर सौर, पवन और जल जैसी हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना होगा। बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और वनों का संरक्षण, ऊर्जा की बचत, सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहनों का अधिक उपयोग, प्लास्टिक प्रदूषण में कमी तथा उद्योगों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन पर प्रभावी नियंत्रण आवश्यक है।

साथ ही, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए देशों के बीच सहयोग, वैज्ञानिक अनुसंधान और जन-जागरूकता को भी बढ़ावा देना होगा। यदि आज ठोस और प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाली पीढ़ियों को और भी गंभीर जलवायु संकट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए प्रकृति के साथ संतुलित विकास का मार्ग अपनाकर ही पृथ्वी को सुरक्षित, स्वच्छ और रहने योग्य बनाया जा सकता है।

सड़क दुर्घटनाओं की चौंकाती हकीकत

भारत में सड़क दुर्घटनाओं में कमी न आना बेहद दुर्भाग्यजनक है। कई वर्षों के आधिकारिक सरकारी आंकड़े बताते हैं कि लाख कोशिशों के बावजूद आशातीत सफलता न मिलना, कहीं-न-कहीं सड़क पर चलने वालों की मनोदशा पर भी निर्भर करता है। इसी चलते हर रोज देश में कहीं-न-कहीं से भीषण सड़क दुर्घटनाओं के दुखद समाचार मिलते रहते हैं। भारत सरकार की परिभाषा में एक से ज्यादा लोगों की मौत को भीषण सड़क हादसा माना जाता है। सड़क हादसों में बेवजह हजारों लोगों की जान हर वर्ष जाती है।

यदि केवल किसी एक वर्ष के आंकड़ों पर नजर डालें तो काफी चिंताजनक स्थिति है। वर्ष 2023 के दुर्घटनाओं में 71298 घटनाओं में 22109 की मृत्यु हुई जबकि घायलों की संख्या 66280 रही। इस तरह केवल 2023 में 480583 दुर्घटनाओं में 172890 मौतें और 462825 दुर्घटना के शिकार हुए जो अन्य क्षति छोड़कर, मानवीय हैं।

आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि ज्यादातर दुर्घटनाएँ तेज गति, बिना हेलमेट, वाहनों के बीच बिना सुरक्षित दूरी, सुस्ती, नींद के झोंके, वाहन चलाते समय धूम्रपान, शराब या किसी अन्य नशे में होने से दुर्घटनाएँ होती हैं। रात में हमारे वाहन के हेडलाइट्स, टेल लाइट्स और इंडिकेटर्स खराब होने या काम नहीं करने, टायरों का ध्यान नहीं रखने और ज्यादा पुराने, घिसे, कटे-फटे, क्रैक्स से भरपूर टायरों

आंकड़े ही लें तो दुर्घटनाओं की भयावह तस्वीर उभरती है। इस वर्ष 68783 हिट एण्ड रन मामलों में 31209 मौतें हुईं जबकि 54574 लोग घायल हुए। सभी तरह की दुर्घटनाओं का विश्लेषण काफी सोचने और डराने को मजबूर करता है।

इसी वर्ष सड़क पर खड़े वाहनों से टकरा कर 13810 दुर्घटनाओं में 5636 मौतें और 12575 घायल हुए। पीछे से टकराने की दुर्घटनाओं में 36804 मौतें 107161 घायल हुए। साइड से टक्कर की 73805 घटनाओं में 20623 मौतें और 74017 घायल हुए। सड़क से नीचे गिरने की 21527 घटनाओं में 10196 लोगों की मृत्यु हुई, 20719 घायल हुए। स्थिर वस्तु से टकराने की 17451 घटनाओं में 8291 मृत्यु और 16416 घायल हुए। जबकि वाहन पलटने की 18905 घटनाओं में 9124 की मृत्यु और 21216 घायल हुए। वहीं, आमने-सामने की टक्कर की 84348 दुर्घटनाओं में 28989 की मृत्यु और 89867 घायल हुए। अन्य का उपयोग, बरसात के मौसम में घिसे टायरों पर ट्रैक्शन कम होने से वाहन फिसलने और प्रायः ब्रेक नहीं लगने से भी दुर्घटनाएं आम हैं। ब्रेक की नियमित जांच से कई तरह की दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बातें भी ध्यान भटकाता है।

गंतव्य तक पहुंचने की जल्दी में आगे निकलने की होड़ और ओवरटेक भी वजह है। छोटी सड़कों पर ध्यान नहीं देना कि कहीं सामने दूसरा वाहन तो नहीं आ रहा? जबकि हाइवे पर इंडीकेटर का सही उपयोग नहीं करना, दुर्घटनाओं का सबब बनता है। ओवरटेक की होड़ से भी दुर्घटनाएँ होती हैं। यह सभी वो छोटे-छोटे उपाय व यातायात के नियम हैं जिन्हें हम जानते तो हैं पर अमल में नहीं लाते हैं। थोड़ी सतर्कता, थोड़ी सजगता से बड़ी-बड़ी दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। इसीलिए यातायात विभाग का बेहद लोकप्रिय नारा है- दुर्घटना से देर भली।

असम ने बाढ़ प्रभावितों के राहत, पुनर्वास के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी: हिमंत

गुवाहाटी, एजेंसी।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य सरकार ने भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों के राहत एवं पुनर्वास के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी है। राज्य सरकार ने अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) के समक्ष अपनी मांग रखी। इस दल ने बुधवार को ऊपरी असम के बाढ़ प्रभावित जिलों का अपना चार दिन का दौरा संपन्न किया था।

शर्मा ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, इस साल आई बाढ़ अभूतपूर्व है और इसने भारी तबाही मचाई है। हमारी 'डबल इंजन' सरकार लोगों की परेशानी को कम करने के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ऊपरी असम में आई बाढ़ को असामान्य करार देने की मांग की है, साथ ही नुकसान के आकलन और मदद के लिए लचीले नियमों की भी मांग की है।शर्मा ने कहा कि इसमें शिवसागर, चराइदेव, जोरहाट और गोलाघाट के लिए एक खास केंद्रीय सहायता पैकेज की मांग की गई, जिसमें राहत, आवास, अवसंरचना और आजीविका को फिर से बहाल करना शामिल है।उन्होंने कहा कि असम ने पूर्वोत्तर में आपदा जोखिम कम करने के लिए एक तंत्र बनाने की भी मांग की, ताकि असम और सात पड़ोसी राज्यों में आपदा प्रबंधन के सभी चरणों में क्षेत्रीय तालमेल को मजबूत किया जा सके।

ई20 पेट्रोल ईंधन की खपत को दो से छह प्रतिशत तक घटा सकता है : गडकरी

नई दिल्ली, एजेंसी।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संसद को बताया कि 20 प्रतिशत एथनॉल मिश्रित पेट्रोल (ई20) वाहनों में ईंधन की खपत को 2 से 6 प्रतिशत तक घटा सकता है।

हालांकि, केंद्रीय मंत्री ने तर्क दिया कि 'डायनमोमीटर' पर इंजन की मजबूती की जांच और सड़क पर वाहन के परीक्षणों में ई20 के कारण कोई समस्या देखने को नहीं मिली है।

लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, गडकरी ने कहा कि ई10 ईंधन की तुलना में ई20 ईंधन के उपयोग से बेहतर 'एक्सेलरेशन' होता है, परिवहन बेहतर व सुगम होता है तथा लगभग 30 प्रतिशत कम कार्बन उत्सर्जन होता है।

गडकरी ने कहा कि बीएस3, बीएस4 और बीएस6 ई10 (पेट्रोल) वाले दोपहिया और चारपहिया वाहनों पर ई20 के असर का पता लगाने के लिए ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई), सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने संयुक्त रूप से एक अध्ययन किया।

उन्होंने कहा कि इस अध्ययन में संबंधित प्रमाणन आवश्यकताओं के अनुसार, मानक परीक्षण और मूल उपकरण विनिर्माताओं के साथ मिलकर तैयार किए गए परीक्षण प्रोटोकॉल शामिल थे।

ई20 पेट्रोल (80 प्रतिशत पेट्रोल, 20 प्रतिशत एथनॉल) का उपयोग शुरू किये जाने पर विपक्षी पार्टियों और कुछ उपभोक्ता समूहों ने आलोचना की है।

उन्होंने उन पुरानी गाड़ियों पर इसके प्रभाव को लेकर चिंता जताई है जिन्हें खास तौर पर 20 प्रतिशत एथनॉल मिश्रण वाले ईंधन के लिए नहीं बनाया गया था।

आलोचकों ने सवाल किया है कि क्या सभी गाड़ियां ई20 से बखूबी परिचालित हो सकती। उन्होंने कम ईंधन दक्षता और रखरखाव पर अधिक खर्च की आशंका जताई है, और इंजन या ईंधन प्रणाली में कोई समस्या आने पर दायित्व के बारे में स्पष्ट जानकारी मांगी है।

सरकार का कहना है कि यह बदलाव कई चरणों में किया गया है और इसके लिए व्यापक परीक्षण किया गया है। ऑटोमोबाइल कंपनियों ने कहा है कि वे ई20 ईंधन का इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के लिए वारंटी दावे को पूरा करती रहेंगी। विपक्षी पार्टियों ने गाड़ियों की अनुकूलता और ग्राहकों की सुरक्षा को लेकर बार-बार अधिक पारदर्शिता की मांग की है।

गडकरी ने बताया कि 20 करोड़ से अधिक दोपहिया वाहन और 3 करोड़ से ज्यादा पेट्रोल कारें इन मिश्रित ईंधन से परिचालित हो रही हैं, और एथनॉल मिश्रण की वजह से व्यापक रूप से इंजन में गड़बड़ी आने या गाड़ी खराब होने का कोई भी प्रामाणिक साक्ष्य नहीं मिला है।

भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले अब राम मंदिर की बात कर रहे हैं: भाजपा

नई दिल्ली, एजेंसी।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बृहस्पतिवार को समाजवादी पार्टी (सपा) पर अयोध्या में राम मंदिर को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जो लोग भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाते थे और राम जन्मभूमि आंदोलन का मज़ाक उड़ाते थे, वे अब मंदिर के मुद्दे पर चिंता जताने का दिखावा कर रहे हैं।

भाजपा ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार इस मामले को संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ संभाल रही है।

यह बयान उस वक्त आया जब समाजवादी पार्टी के सांसदों ने बृहस्पतिवार को संसद भवन परिसर में राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के विरोध में प्रदर्शन किया।

भाजपा के राज्यसभा सदस्य एवं पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी जिस तरह की राजनीति करने की कोशिश कर रही है, वह बेहद निंदनीय है।

उन्होंने कहा, यह बिल्कुल साफ है कि सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार इस मामले को पूरी संवेदनशीलता और सावधानी के साथ संभाल रही है।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सपा और उसके सहयोगी भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाते हैं और राम जन्मभूमि आंदोलन का मजाक उड़ाते हैं।

त्रिवेदी ने कहा, ये वही लोग हैं, जो कहते थे कि अयोध्या का कोई इतिहास ही नहीं है। ये वही लोग हैं, जिन्होंने दावा किया था कि भगवान श्री राम का कभी अस्तित्व ही नहीं था। ये वही लोग हैं, जिन्होंने इस मुद्दे का मजाक उड़ाते हुए पूछा था कि क्या राजा दशरथ के इतने सारे महल थे और वे कहां स्थित थे।''

उन्होंने कहा, ''ये वही लोग हैं, जिन्होंने राम भक्त 'कार सेवकों' के खून से सरयू नदी को लाल कर दिया था। त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने अयोध्या का 'अपमान' किया, वे अब मंदिर के मुद्दे पर चिंता जताने का दावा कर रहे हैं; वे सनातन धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जिन लोगों ने अयोध्या का अपमान किया, अयोध्या को बदनाम किया, अयोध्या को शर्मसार किया और सरयू को रक्त-रंजित किया, वे अब चिंता जताने का ढोंग कर रहे हैं।

जयपुर में जुटेंगे राष्ट्रमंडल देशों के न्यायाधीश

जयपुर, एजेंसी। राजधानी में 31 जुलाई से 2 अगस्त तक कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ विषय पर तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें मेडिएशन, रूल ऑफ लॉ तथा न्याय तक प्रभावी एवं समावेशी पहुंच से जुड़े समकालीन वैश्विक विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत 31 जुलाई को सायं 6 बजे सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (आरएसएलएसए), कॉमनवेल्थ लॉयर्स एसोसिएशन (सीएलए), सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) तथा मेडिएटर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में यह सम्मेलन जयपुर स्थित होटल द ललित में होगा।

उप्र के अगले विधानसभा चुनाव में 250 से ज्यादा सीटें जीतेगी सपा : अखिलेश

बदायूं (उप्र), एजेंसी।

समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में 250 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि उन्होंने इन चुनाव के लिए सभी प्रत्याशी अपने 'मन' में तय कर लिये हैं।

यादव सहसवान सीट से पांच बार विधायक रह चुके पूर्व मंत्री ओमकार सिंह के निधन के बाद उनके आवास पर श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से बातचीत में यादव ने दावा किया कि उनकी पार्टी अगले साल के शुरू में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 250 से अधिक सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार, गाड़ियों के लिए हानिकारक एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाकर बेचने, खराब कानून व्यवस्था, पटरी से उतरी स्वास्थ्य व्यवस्था जैसे मुद्दों को जनता के सामने रखेगी।

सार समाचार

राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा पर बनेगी आधुनिक शौचालय सुविधा

नई दिल्ली,एजेंसी। स्वच्छता और यात्री सुविधा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाज़ा पर विश्वस्तरीय सार्वजनिक शौचालय सुविधाएं विकसित करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि एनएचएआई ने इसके लिए नया प्रदर्शन आधारित ढांचा तैयार किया है, जिसमें स्वच्छता, डिजिटल निगरानी और यात्री केंद्रित रखरखाव पर ध्यान दिया गया है। इस पहल के तहत पुराने शौचालय ब्लॉकों का नवीनीकरण किया जाएगा और नए शौचालय बनाए जाएंगे। इनका डिजाइन स्वदेशी और टिकाऊ होगा, जिसमें हरित भवन मानकों का पालन किया जाएगा। नई व्यवस्था में इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित लाइव टेलीमेट्री सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे वास्तविक समय में रखरखाव की निगरानी हो सकेगी।

कोयंबटूर विस्फोट मामले में ईडी की देश के 16 ठिकानों पर छापेमारी

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वर्ष 2022 के कोयंबटूर बम विस्फोट मामले में आतंकी फंडिंग की जांच के सिलसिले में गुरुवार को चेन्नई, कोयंबटूर, हैदराबाद और मुंबई में 16 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। जांच में सामने आया कि विस्फोट के आरोपितों ने फर्जी कोविड-19 वैक्सीन प्रमाणपत्र घोटाले और कोवाई अरबी कॉलेज के नाम पर चंदा एवं फर्जी निवेश के जरिए धन जुटाकर आतंकी गतिविधियों को वित्तपोषित किया।

ईडी ने बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत यह कार्रवाई राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विभिन्न प्राथमिकी के आधार पर शुरू की गई जांच के तहत की जा रही है।

जांच एजेंसी के अनुसार, वर्ष 2022 में कोयंबटूर के संगमेश्वरर मंदिर के निकट हुए आत्मघाती कार बम विस्फोट को जमेशा मुबीन और उसके साथियों ने अंजाम दिया था। यह हमला विस्फोटक पदार्थों से भरी संशोधित मारुति कार का इस्तेमाल कर प्रतिबंधित आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस) से प्रेरित आतंकी हमले के रूप में किया गया था।

ईडी की जांच में सामने आया है कि आरोपितों ने आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के दो प्रमुख तरीके अपनाए।

महानदी में मध्यम स्तर की बाढ़ की आशंका

भुवनेश्वर, एजेंसी।

ओडिशा में बृहस्पतिवार को भी हाई अलर्ट जारी रहा। राज्य के चार उत्तरी जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी रही जबकि महानदी और उसकी सहायक नदियों में 'मध्यम दर्जे की बाढ़' के मद्देनजर अधिकारी तैयारियों में जुटे हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता (इंजीनियर-इन-चीफ) ने कहा कि बृहस्पतिवार रात से अगले 36 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि महानदी में बाढ़ के जल का सबसे अधिक प्रवाह होने की संभावना है।

राउत ने पत्रकारों से कहा, ''हम कटक के पास मुंडाली में 9 लाख से 9.5 लाख क्यूसेक पानी के प्रवाह की उम्मीद कर रहे हैं। बृहस्पतिवार रात से अगले 36 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि महानदी में बाढ़ शीर्ष स्तर पर होगी। इस मानसून के दौरान नदी में पानी की यह सबसे अधिक मात्रा होगी। राउत के अनुसार, महानदी प्रणाली में आठ लाख क्यूसेक से अधिक के प्रवाह को मध्यम दर्जे की बाढ़ माना जाता है।

भारत-म्यांमार बॉर्डर हाट व्यापार के लिए फिर से खुला

इटानगर, एजेंसी। अरुणाचल प्रदेश के व्यापार और वाणिज्य मंत्री, न्याटो डुकाम ने गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में नामपोंग के पास पांसो पास इलाके में भारत-म्यांमार बॉर्डर हाट को फिर से शुरू करने करने के लिए इसका आधिकारिक उद्घाटन किया।

इसका मकसद सीमा-पार व्यापार, आर्थिक गतिविधियों और क्षेत्रीय संबंधों को फिर से मजबूत करना है। इस मौके पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए, मंत्री डुकाम ने इस क्षेत्र के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में व्यापार और वाणिज्य की अहम भूमिका पर जोर दिया।

पोस्ट-फैक्टो पर्यावरणीय मंजूरी के दायरे के विस्तार स्वीकार्य नहीं: कांग्रेस

नई दिल्ली, एजेंसी।

कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह किसी कार्य के पूरा होने के बाद पर्यावरणीय मंजूरी (पोस्ट-फैक्टो) देने के दायरे का विस्तार करने के हर प्रयास का विरोध करती रहेगी और पर्यावरण कानून के मूल सिद्धांतों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहेगी।

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने उच्चतम न्यायालय के एक फैसले के संदर्भ में यह टिप्पणी की।

न्यायालय ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में केंद्र सरकार के 2021 के उस कार्यालय ज्ञापन को रद्द कर दिया, जिसके तहत बिना पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के शुरू की गई परियोजनाओं को पूर्वप्रभावी पर्यावरणीय मंजूरी देने की व्यवस्था बनाई गई थी। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने सर्वसम्मत फैसले में सरकार को कुछ राहत भी प्रदान की। पीठ ने कहा कि यह फैसला भविष्य के प्रभाव से लागू होगा और पहले से पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) प्राप्त परियोजनाएं इससे प्रभावित नहीं होंगी। कांग्रेस महासचिव और पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि मई 2025 में उच्चतम न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने पर्यावरण कानून के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था।

उन्होंने कहा, ''पीठ ने माना था कि पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी अनिवार्य है और 2017 की अधिसूचना तथा 2021 के कार्यालय ज्ञापन के जरिए बनाई गई बाद में मंजूरी देने की व्यवस्था गैरकानूनी कार्यों को बढ़ावा देती है, पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) प्रक्रिया को कमजोर करती है तथा सतत विकास और स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है।''

रमेश ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर करते हुए दलील दी कि इससे बिना पूर्व मंजूरी शुरू की गईं करोड़ों रुपये की परियोजनाएं प्रभावित होंगी। उनका कहना है, उच्चतम न्यायालय का कल सुनाया गया फैसला सही दिशा में उठाया गया कदम है। हालांकि, उन्होंने कहा कि इस फैसले में सरकार को असाधारण परिस्थितियों में बाद में पर्यावरणीय मंजूरी देने के लिए वैधानिक व्यवस्था बनाने की अनुमति भी दी गई है और इन परिस्थितियों को परिभाषित करने का अधिकार भी सरकार के पास होगा।

नीट के मामले पर छात्रों को गुमराह कर रहे हैं राहुल : चुघ

नई दिल्ली, एजेंसी।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी नीट मुद्दे पर छात्रों की चिंताओं का समाधान करने के बजाय उन्हें गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं।

चुघ ने यह भी कहा कि भारत और सनातन के खिलाफ टिप्पणी करना राहुल गांधी की आदत बन चुकी है।

भाजपा नेता की यह टिप्पणी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उस आरोप के एक दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की ज्यादती और फायरिंग के लिए जिम्मेदार हैं। इस मुद्दे को लेकर सत्तापक्ष ने उनपर पलटवार किया और कहा कि उन्हें (राहुल को) माफी मांगनी चाहिए।

चुघ ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा, राहुल गांधी को छात्रों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने छात्रों के भविष्य पर राजनीति करने का तुच्छ प्रयास किया है। उन्होंने छात्रों की वास्तविक समस्याओं के समाधान पर एक शब्द भी नहीं कहा। इसके बजाय उन्होंने केवल भ्रम फैलाने और मुद्दे को उलझाने का प्रयास किया।

भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी देश और विदेश, दोनों जगह, भारत और सनातन के खिलाफ लगातार दुष्प्रचार करते हैं और इसके लिए उन्हें (कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को) देश से माफी मांगनी चाहिए।

चुघ ने कहा, विदेशी टूलकिट का हिस्सा बनकर वह सनातन, हिंदू धर्म, भारत और उसकी संस्थाओं का अपमान करते हैं। यह उनकी आदत बन गई है। उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भदोही का नाम बदलकर संत रविदास नगर किए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए चुघ ने इसे संत गुरु रविदास के प्रति उचित सम्मान बताया। चुघ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा सरकार ने पहले संत रविदास नगर का नाम हटाकर संत रविदास और उनके अनुयायियों का अपमान किया था।

राष्ट्रपति से मिलीं केन्द्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर

भोपाल,एजेंसी। मध्य प्रदेश के धार से सांसद और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने गुरुवार को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। उन्होंने राष्ट्रपति को अक्टूबर माह में धार में प्रस्तावित महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। केन्द्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर ने सोशल मीडिया एक्स पर उक्त जानकारी साझा करते हुए बताया कि आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से शिष्टाचार भेंट कर उन्हें प्रस्तावित वीरांगना महारानी रानी दुर्गावती के जन्मोत्सव समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पधारने हेतु सादर आमंत्रित किया।

सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाना ठीक नहीं : प्रफुल्ल पटेल

नई दिल्ली, एजेंसी।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने बृहस्पतिवार को कहा कि पिछले कुछ दिनों में प्रश्नपत्र लीक मामले और उसके बाद हुए घटनाक्रम से केवल छात्र ही परेशान नहीं हुए बल्कि सरकार को भी पीड़ा हुई है और 'लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026' इसी पीड़ा का परिणाम है।

उन्होंने कहा कि सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाना ठीक नहीं है।

राज्यसभा में 'लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026' पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि युवाओं का भविष्य देश का भविष्य है और भारत को विश्व में युवा देश माना जाता है क्योंकि देश में युवाओं की आबादी 65 फीसदी से अधिक है।

उन्होंने कहा पिछले कुछ दिनों में जो कुछ घटनाएं हुईं, उनसे सरकार को भी पीड़ा हुई है और यह विधेयक उसी का परिणाम है। सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाना ठीक नहीं है।

पटेल ने कहा कि पिछले 12 साल में शिक्षा व्यवस्था में आया बदलाव नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज युवाओं के लिए अवसरों की वृद्धि हुई है जिसका मुख्य कारण है कि उनके लिए विविध पाठ्यक्रम आज उपलब्ध हैं और इसमें भी आगे की संभावनाएं देखी जा रही हैं।

सरकार प्रश्न पत्र लीक समस्या में रोग का नहीं लक्षणों का इलाज कर रही है : ब्रिटास

नई दिल्ली, एजेंसी।

राज्यसभा में बृहस्पतिवार को माकपा सांसद जॉन ब्रिटास ने प्रश्न पत्र लीक समस्या को रोकने के लिए सरकार द्वारा लाये गये विधेयक को अपर्याप्त बताते हुए कहा कि इसमें रोग नहीं लक्षणों का इलाज किया जा रहा है।

उच्च सदन में 'लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026' पर चर्चा में भाग लेते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटास ने कहा कि वह जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन में शामिल होने के लिए गये थे। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र लीक होने से न केवल छात्र बल्कि उनके माता-पिता को भी बहुत निराशा होती है।

उन्होंने कहा कि इस विधेयक से प्रश्न पत्र लीक होने की समस्या का हल नहीं निकलेगा क्योंकि इसमें रोग नहीं उसके लक्षणों का इलाज किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि यह सरकार केवल समिति पर समिति बनाती रही है। उन्होंने इस बारे में मशहूर हास्य कलाकार जसपाल भट्टी के टीवी सीरियल 'उल्टा पुल्टा' का उदाहरण दिया जिसमें हर समस्या के लिए सरकार के पास एक ही हल यानी समिति बनाने का उपाय होता है।

ब्रिटास ने कहा कि देश में करोड़ों रूपये का कोचिंग उद्योग कारोबार हो गया है और उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है।

उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें बीमा कंपनी पर मुआवजे का दायित्व डाला गया था

अमान्य ड्राइविंग लाइसेंस पर बीमा कंपनी नहीं देगी दुर्घटना मुआवजा

नई दिल्ली, एजेंसी।

उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि यदि दुर्घटना के समय वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस वैध नहीं था या उसका नवीनीकरण नहीं हुआ था, तो बीमा कंपनी मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि दुर्घटना करने वाला वाहन बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के चलाया जा रहा था, तो बीमा कंपनी पर मुआवजे का दायित्व नहीं डाला जा सकता।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि बिना वैध लाइसेंस के वाहन चलाने की प्रवृत्ति के कारण दुर्घटना के मामलों में चालक, वाहन मालिक या दोनों को भारी-भरकम मुआवजा चुकाने की नौबत आ सकती है। न्यायालय ने इस संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए देशव्यापी अभियान चलाने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा राज्यों के परिवहन विभागों से सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और यातायात नियमों के पालन को सुदृढ़ करने के लिए देशव्यापी जागरूकता अभियान चलाने को कहा।

पीठ ने मंत्रालय और राज्यों को सोशल मीडिया सहित विभिन्न माध्यमों के जरिए व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाने तथा ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने और उसके नवीनीकरण की प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित बनाने का भी निर्देश दिया।

शीर्ष अदालत ने ड्राइविंग स्कूलों के नियमन, उन्हें किफायती बनाने तथा लाइसेंस के लिए आवेदन और परीक्षा की प्रक्रिया को क्षेत्रीय भाषाओं में सुलभ बनाने के लिए भी तत्काल सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया।

न्यायमूर्ति करोल ने फैसले में कहा, भारत सरकार का सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा राज्यों के संबंधित विभागों को जागरूकता अभियान, सोशल मीडिया और अन्य सभी माध्यमों के जरिए लोगों को इस विषय के महत्व से अवगत कराना चाहिए, नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के उपाय करने चाहिए और लाइसेंस जारी करने तथा उसके नवीनीकरण की प्रक्रिया को भी सुव्यवस्थित बनाना चाहिए।

उन्होंने कहा, ड्राइविंग स्कूलों के नियमन, उनकी वहनीयता तथा आवेदन और परीक्षा की प्रक्रिया को क्षेत्रीय भाषाओं में सुलभ बनाने जैसे मुद्दों पर भी तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें बीमा कंपनी पर मुआवजे का दायित्व डाला गया था।

यह मामला वर्ष 2009 की एक सड़क दुर्घटना से संबंधित है, जिसमें ओम प्रकाश द्वारा चलाया जा रहा एक वाहन दोपहिया वाहन से टकरा गया था।

सार समाचार

एफसीआरए संशोधन विधेयक के खिलाफ विरोध मार्च का किया आह्वान

आइज़ोल,एजेंसी। मिजोरम में चर्चों के संगठन काउंसिल ऑफ चर्चेज इन मिज़ोरम ने संसद के मौजूदा मानसून सत्र में संभावित तौर पर प्रस्तावित विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक या एफसीआरए संशोधन विधेयक के खिलाफ 11 अगस्त को यहां एक बड़े विरोध मार्च की घोषणा की है। काउंसिल का आरोप है कि इस प्रस्तावित कानून के लागू होने से गिरजाघरों और स्वयंसेवी संगठनों के कामकाज पर बुरा असर पड़ सकता है। गुरुवार को मीडिया को संबोधित करते हुए काउंसिल सीसीएम के नेताओं ने प्रस्तावित कानून को लेकर मिज़ोरम सरकार के ढुलमुल रवैये पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शायद इस मुद्दे की गंभीरता को पूरी तरह से नहीं समझ पा रही है, क्योंकि इसके सीधे परिणाम उसे नहीं भुगतने पड़ेंगे, जबकि विदेशी दान प्राप्त करने वाले गिरजाघर और धर्मार्थ संगठन इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे।

कोरबा में आवारा मवेशियों के खिलाफ अभियान तेज

कोरबा, एजेंसी। शहर की सड़कों पर घूमने वाले आवारा एवं घुमंतू मवेशियों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने विशेष अभियान शुरू किया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुणाल दुदावत के निर्देश पर नगर निगम और पशुधन विकास विभाग की संयुक्त टीम द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मवेशियों की धरपकड़ और सुरक्षा संबंधी कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि सड़कों पर खुले में घूमने वाले मवेशियों को तत्काल पकड़ा जाए और उनके मालिकों की पहचान कर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्रवाई की जाए। प्रशासन का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और शहर की यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाना है।

उद्योगों में स्थानीय किसानों और ग्रामीणों को प्राथमिकता से रोजगार मिले: डॉ. यादव

उज्जैन, एजेंसी।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित होने वाले उद्योगों में स्थानीय किसानों और ग्रामीणों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जाए, ताकि स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलने के साथ क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरुवार को उज्जैन प्रवास के दौरान विक्रम उद्योगपुरी का निरीक्षण कर औद्योगिक विकास एवं निवेश परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप फसलों के उत्पादन के लिए प्रेरित किया जाए।

जिससे उनकी आय बढ़े और उद्योगों को स्थानीय स्तर पर आवश्यक कच्चा माल उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की उद्योग-अनुकूल नीतियों, आधुनिक अधोसंरचना और निवेशकों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास तेजी से आगे बढ़ रहा है। मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी) के कार्यपालक निदेशक राजेश राठौड़ ने

मुख्यमंत्री को जिले में संचालित एवं प्रस्तावित औद्योगिक परियोजनाओं, औद्योगिक अधोसंरचना विकास, भूमि आवंटन और निवेश की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने लगभग 1,266 करोड़ रुपये के निवेश से स्थापित मेसर्स पेप्सिको इंडिया लिमिटेड की अत्याधुनिक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का निरीक्षण भी किया। इस इकाई का वर्चुअल लोकार्पण उन्होंने गुरुवार को किया। इस परियोजना से लगभग 800 प्रत्यक्ष तथा बड़ी संख्या में अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है।

उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में 50.05 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन वर्किंग वूमेन हॉस्टल का भी निरीक्षण किया। लगभग 1,500 महिलाओं की आवासीय क्षमता वाले

- मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप फसलों के उत्पादन के लिए प्रेरित किया जाए।

इस परिसर को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षित एवं आधुनिक आवासीय सुविधाएं उपलब्ध होने से प्रदेश में महिला कार्यबल की भागीदारी बढ़ेगी और महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिलेगी।

कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने बताया कि पिछले ढाई वर्षों में उज्जैन जिले में 246 नई औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटित की गई है, जिनसे लगभग 16,150 करोड़ रुपये के निवेश तथा 14,500 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि लगभग 773 एकड़ क्षेत्र में विकसित विक्रम उद्योगपुरी में अब तक 94 भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं, जिनसे लगभग 6,480 करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद है।

फडणवीस ने 'ड्रग-फ्री मुंबई' अभियान शुरू किया

मुंबई, एजेंसी।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई को नशीले पदार्थों से मुक्ति दिलाने के लिए गुरुवार को 'ड्रग-फ्री मुंबई' अभियान शुरू किया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ इस लड़ाई को न केवल कानून-व्यवस्था की प्राथमिकता बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा बताया और इस बात पर जोर दिया कि देश का भविष्य युवाओं की मजबूती और भलाई पर निर्भर करता है। उन्होंने विरोधी ताकतों के द्वारा समाज के कमजोर वर्गों को नशीले पदार्थों की लत की ओर धकेलकर भारत को अंदर से कमजोर करने की कोशिश के खिलाफ चेतावनी दी। मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस बहुआयामी पहल की शुरुआत करते हुए कहा कि नशीले पदार्थों की समस्या को सिर्फ पुलिसिंग से खत्म

नहीं किया जा सकता।

उन्होंने नशा-मुक्त माहौल बनाने के लिए परिवारों, शिक्षण संस्थानों, सिविल सोसायटी और लोगों को शामिल करते हुए एक सामूहिक सामाजिक आंदोलन का आह्वान किया। श्री फडणवीस ने पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्यों के संकटों का उदाहरण देते हुए युवा पीढ़ी के साथ समझौता करने से पूरे देश की बुनियादी सुरक्षा और स्थिरता के खतरे में पड़ने को आगाह किया। राज्य प्रशासन ने सख्त 'जीरो-टॉलरेंस' नीति लागू की है, जिसके तहत नशीले पदार्थों के उत्पादन, तस्करी के नेटवर्क और स्थानीय वितरण चैनलों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है और साथ ही विशेष मादक पदार्थ निरोधक इकाइयां को मजबूत किया जा रहा है।

यह अभियान स्कूलों और कॉलेजों तक भी पहुंचाया जा रहा है, जिसके लिए संस्थागत काउंसलिंग समितियां बनाई गई हैं। इनका मकसद परिसर को पूरी तरह नशा-मुक्त बनाना और बचाव के बारे में जागरूकता फैलाना है। श्री फडणवीस ने युवाओं से हानिकारक आदतों को छोड़ने का आग्रह करते हुए उन्हें अपनी ऊर्जा देशभक्ति, कड़ी मेहनत और महत्वाकांक्षी करियर लक्ष्यों में लगाने के लिए प्रेरित किया, ताकि वे एक प्रगतिशील महाराष्ट्र और भारत की असली ताकत बन सकें।

भोपाल में एसी ई-बस सेवा शुरू, तीन रूटों पर दौड़ीं 10 इलेक्ट्रिक बसें

भोपाल, एजेंसी।

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में गुरुवार से वातानुकूलित (एसी) इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारंभ हो गया। टिकटिंग सॉफ्टवेयर की परीक्षण प्रक्रिया और ट्रायल रन पूरा होने के बाद पहले चरण में तीन मार्गों पर 10 ई-बसों का संचालन शुरू किया गया है। इन बसों का किराया वर्तमान सिटी बसों के समान रखा गया है, जो सात रुपये से 40 रुपये तक है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार ई-बसों का संचालन चिरायु हॉस्पिटल से डीबी मॉल मेट्रो स्टेशन वाया बैरागढ़-चिचली, चिरायु हॉस्पिटल से डीबी मॉल मेट्रो स्टेशन तथा डीबी मॉल मेट्रो स्टेशन से कोच फैक्ट्री मार्ग पर किया जा रहा है। बसें शहर के सभी निर्धारित बस स्टॉप पर रुक रही हैं, हालांकि फिलहाल इनके संचालन का समय निर्धारित किया जा रहा है। भोपाल में अब तक 30 इलेक्ट्रिक बसें पहुंच चुकी हैं, जिनमें से पहले चरण में 10 बसों को यात्रियों के लिए संचालित किया गया है। दूसरे चरण में 10 और बसें शुरू की जाएंगी। आगामी 15 अगस्त को प्रदेश स्तर पर औपचारिक लोकार्पण के बाद सभी 30 बसें नियमित रूप से सड़कों पर दौड़ेंगी। नगर निगम के अनुसार अगले 10 से 12 दिनों में 20 और इलेक्ट्रिक बसें भोपाल पहुंचने की संभावना है।

लोकतंत्र को भीड़तंत्र में नहीं बदलना चाहिए: शांता कुमार

पालमपुर,एजेंसी। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने पेपर लीक रोकने वाले कड़े कानून की संसद में मंज़ूरी का स्वागत किया है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है जो परीक्षा के पेपर लीक होने की समस्या पर प्रभावी तरीके से रोक लगाएगा। बुधवार को यहां जारी एक बयान में कुमार ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में पेपर लीक और भ्रष्टाचार के खिलाफ लंबे संघर्ष के बाद दो अहम घटनाक्रम हुए हैं। पहला, लोकसभा द्वारा पेपर लीक को रोकने के लिए एक कड़ा कानून पारित किया जाना। भाजपा नेता ने कहा कि यह कानून पेपर लीक जैसे गंभीर अपराध से सख्ती से निपटेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता बहाल करने में मदद करेगा। कुमार ने कहा कि दूसरी अहम बात इस मुद्दे के लिए लंबे समय तक चलने वाले समाधान सुझाने के मकसद से छह जाने-माने राष्ट्रीय विद्वानों की एक समिति का गठन करना था।

जेपीएससी के तीनों सदस्यों को तत्काल बर्खास्त कर जेल भेजे सरकार: साहू

रांची, एजेंसी।

झारखंड के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने हेमंत सरकार से जेपीएससी के तीनों सदस्यों को बर्खास्त करते हुए उनपर मुकदमा दर्ज कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजने की मांग की है। साहू ने साथ ही इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग को दुहराया है। साहू ने कहा कि जेपीएससी अध्यक्ष ने इस्तीफा तो दिया लेकिन इसके तीनों सदस्य अभी भी अपने पद पर बने हुए हैं। जब तक ये सदस्य अपने पद पर बने रहेंगे तब तक इस महाघोटाले की निष्पक्ष जांच

की कल्पना भी बेमानी है।

साहू ने कहा कि जेपीएससी सहित सभी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी मामले में राज्य सरकार की मंशा प्रारंभ से ही ठीक नहीं है। छात्रों को न्याय देने की बजाय भ्रष्टाचार से जुड़े इन सभी मामलों की लीपापोती कैसे की जा सके, हेमंत सरकार केवल इस प्रपंच में ही दिन रात तिकड़म भिड़ाने में अपनी ऊर्जा खपत कर रही है। सरकार के सारे फैसले इसकी गवाही भी देते हैं। जेपीएससी मामले में अध्यक्ष एल ख्यांगते ने इस्तीफा दिया लेकिन राज्य सरकार के स्तर से उनपर क्या कार्रवाई हुई, उन पर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई?

तत्कालीन अध्यक्ष की गिरफ्तारी सहित तीनों सदस्यों की बर्खास्तगी एवं उनकी गिरफ्तारी भी तत्काल सुनिश्चित हो। साहू ने कहा कांग्रेस-झामुमो की दोहरी राजनीति पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। थोड़ा बहुत जो टालमटोल झारखंड सरकार कर ले, परंतु इस पूरे मामले की सीबीआई जांच तो उन्हें करानी ही होगी। देर सबेर गड़बड़ियों से जुड़ी सारी परत सार्वजनिक होगी। जेएसएससी, जेपीएससी एवं उत्पाद सिपाही भर्ती घोटालों के विरोध में बीते बुधवार को संसद भवन के मकर द्वार पर हमारी पार्टी के झारखंड के सांसदों ने आवाज बुलंद किया है।

कल यानि शुक्रवार को संसद भवन परिसर में ही झारखंड के सांसदों का एक घंटे का मौन उपवास है। भाजपा, छात्रों की इस लड़ाई के साथ हर कदम खड़ी है।

महानदी विवाद नहीं, छत्तीसगढ़-ओडिशा की साझा समृद्धि का आधार बने: साय

रायपुर/नई दिल्ली, एजेंसी।

महानदी जल बंटवारे से जुड़े विषयों के सौहार्दपूर्ण एवं स्थायी समाधान की दिशा में गुरुवार को नई दिल्ली स्थित श्रमशक्ति भवन में एक महत्वपूर्ण पहल हुई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच महानदी जल विवाद के सम्बन्ध में बैठक आयोजित हुई।

बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू सहित दोनों राज्यों के वरिष्ठ प्रशासनिक एवं तकनीकी अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि महानदी छत्तीसगढ़ और ओडिशा दोनों राज्यों की साझा जीवनरेखा है। इसका जल किसानों की आजीविका, पेयजल व्यवस्था, औद्योगिक विकास, पर्यावरण संरक्षण

और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार इस बैठक को किसी विवाद की निरंतरता नहीं बल्कि समाधान की नई शुरुआत के रूप में देखती है। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के बीच संवाद और सहयोग का जो वातावरण बना है, वह भविष्य में स्थायी एवं व्यावहारिक समाधान का मजबूत आधार बनेगा।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ओडिशा की सिंचाई, पेयजल तथा हीराकुंड परियोजना से जुड़ी आवश्यकताओं का पूरा सम्मान करती है। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के किसानों, आदिवासी अंचलों, सूखा प्रभावित क्षेत्रों तथा राज्य की भविष्य की विकास आवश्यकताओं को भी समान संवेदनशीलता के साथ देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के हित एक-दूसरे के विरोध में नहीं, बल्कि परस्पर पूरक हैं और समाधान भी ऐसा होना चाहिए जिससे किसी भी पक्ष के हित प्रभावित न हों।

तीन महीने में नशा खत्म करने का केजरीवाल का वादा निकला झूठा: ढिल्लों

चंडीगढ़,एजेंसी। पंजाब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने प्रदेश में बढ़ते नशे के संकट को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि भगवंत मान सरकार का बहुचर्चित 'युद्ध नशों विरुद्ध' अभियान पूरी तरह विफल साबित हुआ है।

उन्होंने कहा कि मोहाली की अंब साहिब कॉलोनी में पिछले 18 दिनों के दौरान नशे की ओवरडोज से पांच युवकों की मौत ने पंजाब में नशे की भयावह स्थिति को उजागर कर दिया है। ढिल्लों ने अंब साहिब कॉलोनी के प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि यह बेहद दुखद और शर्मनाक है कि एक मां ने नशे की वजह से अपने दोनों पुत्रों को खो दिया, जबकि एक अन्य महिला अपने पति की मौत के बाद दो छोटे बच्चों की अकेले परवरिश करने को मजबूर है।

सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर सख्त हुए धामी

देहरादून, एजेंसी।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन-1905 पर प्राप्त शिकायतों के समाधान में किसी भी तरह की लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को चेतावनी दी कि जन शिकायतों का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक निस्तारण हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। धामी ने गुरुवार को कहा कि शिकायतों के समाधान में उदासीनता स्वीकार नहीं की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सचिवालय में आज सीएम हेल्पलाइन-1905 की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से पेयजल एवं जल जीवन मिशन से संबंधित बड़ी संख्या में लंबित शिकायतों पर नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि एक सप्ताह के भीतर इन शिकायतों का प्रभावी निस्तारण किया जाए। साथ ही जिन अधिकारियों की शिकायतों के

निस्तारण में कार्यवाही शून्य प्रतिशत है, उन्हें तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी करने और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्धारित समय सीमा में जिन शिकायतों का समाधान नहीं हो पा रहा है, उनकी नियमित समीक्षा विभागाध्यक्ष और जिलाधिकारी स्तर पर की जाए। उन्होंने स्पेशल क्लोज, डिमांड, सजेशन और अन्य श्रेणियों में डाली गई शिकायतों की भी गंभीरता से जांच करने को कहा, ताकि वास्तविक शिकायतें प्रभावित न हों।

उन्होंने प्रत्येक सोमवार को जिला स्तर पर जिलाधिकारी, मंडल स्तर पर आयुक्त तथा शासन स्तर पर सचिवों द्वारा समाधान दिवस आयोजित कर जन समस्याओं की नियमित सुनवाई और समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पहले ही महीने से पेंशन शुरू कराने तथा भूमि संबंधी विवादों के प्राथमिकता से निस्तारण पर भी जोर दिया।

समीक्षा बैठक में बताया गया कि 18 अप्रैल से 28 जुलाई के बीच हेल्पलाइन पर 67,843 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें 20,461 शिकायतों का पूर्ण, 31,363 का आंशिक निस्तारण किया गया, जबकि 7,404 शिकायतें प्रक्रियाधीन, 4,061 लंबित और 3,738 स्पेशल क्लोज श्रेणी में हैं। इस अवधि में स्पेशल क्लोज की दर घटकर 5.5 प्रतिशत रह गई है।

मुख्यमंत्री ने सभी सचिवों और जिलाधिकारियों को अगली समीक्षा बैठक से पहले अपने-अपने विभागों की व्यापक समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगली बैठक में केवल शिकायतों की संख्या नहीं, बल्कि उनके गुणवत्तापूर्ण निस्तारण, शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि और विभागीय जवाबदेही के आधार पर समीक्षा की जाएगी। बैठक के दौरान उन्होंने विभिन्न जिलों के शिकायतकर्ताओं से फोन पर बातचीत कर शिकायतों के निस्तारण की स्थिति की भी जानकारी ली।

चंडीगढ़ ट्राइसिटी कैब-ऑटो चालकों का धरना 60 दिन बाद हुआ खत्म

चंडीगढ़,एजेंसी। चंडीगढ़ ट्राइसिटी कैब चालक संघ और जय दुर्गा ऑटो-रिक्शा कल्याण संघ के बैनर तले एग्रीगेटर नीति को सख्ती से लागू कराने की मांग को लेकर सेक्टर-25 रैली ग्राउंड में एक जून से जारी कैब और ऑटो चालकों का धरना आखिरकार प्रशासन की ओर से वार्ता के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। यह आंदोलन 60 दिनों से अधिक समय तक चला। संघ का आरोप है कि चंडीगढ़ की अधिसूचित एग्रीगेटर नीति के अनुसार कंपनियां अधिकतम 20 प्रतिशत कमीशन ही ले सकती हैं।

लेकिन वास्तविकता में करीब 30 प्रतिशत तक कमीशन वसूला जा रहा है। इसके अलावा सीएनजी की बढ़ती कीमतों और परिचालन खर्चों को देखते हुए न्यूनतम किराया दरों में संशोधन, प्राइवेट व्हाइट प्लेट वाहनों को एग्रीगेटर ऐप्स से जोड़ने पर रोक तथा सब्सक्रिप्शन और पास सिस्टम खत्म करने की भी मांग की गई।

बिहार में साइबर क्राइम से भी ज्यादा खतरनाक और तेजी से बढ़ता अपराध मानव तस्करी है

सभी महिला थानों में बनेंगे एक एंटी ट्रैफिकिंग इकाई: डीजीपी

पटना,एजेंसी।

बिहार के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विनय कुमार ने कहा कि राज्य में साइबर अपराध से भी अधिक गंभीर और तेजी से बढ़ता अपराध मानव तस्करी, जिससे निपटने के लिए विशेष और प्रभावी व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता हैडीजीपी श्री कुमार ने पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल भवन के सभागार में मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम 'ट्रैप्ड बिहाइंड द स्कैम' को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में साइबर क्राइम से भी ज्यादा खतरनाक और तेजी से बढ़ता अपराध मानव तस्करी है।उन्होंने कहा कि मानव तस्करी के मामले साइबर अपराध से तीन गुणा अधिक दर्ज होते हैं।

इसे रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है। हर जिले में मौजूद महिला थानों में ही एक एंटी

ट्रैफिकिंग इकाई की स्थापना करने की आवश्यकता है। हर जिले में मानव तस्करी के खिलाफ सेल विकसित किया जाए। ये डीजीपी ने कमजोर वर्ग इकाई को इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार कर भेजने के लिए कहा। इसके तहत सभी जिलों में मौजूद महिला थानों में कम से कम दो इकाई का गठन किया जाए, एक इकाई मानव तस्करी के खिलाफ काम करे और दूसरी इकाई महिला एवं बच्चों के खिलाफ अपराध से जुड़े मामले को देखें। दोनों इकाईयों की कमान इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी संभाले।

जबकि, महिला थाने की कमान डीएसपी रैंक के अधिकारी के पास होनी चाहिए। उन्होंने मानव तस्करी को साइलेंट क्राइम की श्रेणी में रखते हुए कहा कि दूसरे अन्य अपराधों की तरह इस अपराध के जख्म और प्रभाव तुरंत दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन यह लंबे समय तक पीड़ित परिवार के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं। कुमार ने कहा कि बिहार देश में पहला राज्य है, जहां सभी जिलों में इस तरह के मामले देखने के लिए डीएसपी (स्पेशल क्राइम) का पद सृजित हैं और इन पर पदाधिकारी की तैनाती भी है, लेकिन यह व्यवस्था नाकाफी है।

क्योंकि मानव तस्करी अपराध के आयाम तेजी से बदल रहे हैं और इसके पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और विकराल होती जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर कोई गायब बच्चा तीन महीने तक नहीं मिलता है, तो इन मामलों को एंटी ट्रैफिकिंग इकाई में ट्रांसफर कर दिया जाए। डीजीपी कुमार ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से जब गुमशुदा बच्चों को सामान्य अपहरण वाले अपराध की श्रेणी में रखते हुए इनकी तफ्तीश शुरू की गई है, तब से इसमें काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2020 में सामान्य अपहरण के 8 हजार मामले दर्ज किए गए थे। जो 2025 में बढ़कर 24 हजार से अधिक हो गई। यानी पिछले 5 वर्षों में 3 से 4 गुणा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इनकी बरामदगी दर 70 फीसदी है। ट्रैफिकिंग के शिकार बच्चों या महिलाओं की रिकवरी दर कम है। यह गंभीर चिंता का विषय है। इनका विवरण अब केंद्रीय गृह मंत्रालय के स्तर से तैयार 'वात्सल्य पोर्टल' पर अपलोड करना अनिवार्य हो गया है। डीजीपी ने सभी पुलिस पदाधिकारियों से कहा कि बच्चा या महिलाओं के अपहरण या गुमशुदगी के मामलों को बेहद संवेदनशीलता के साथ सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए हल करने की जरूरत है।

इनकी जांच के लिए मानसिकता बदलने की भी जरूरत है। इस तरह के मामलों में तस्कर को अंतिम रूप से सजा दिलाए बिना चैन नहीं लेना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि इन मामलों की गवाही में सभी पदाधिकारी को समय निकाल कर प्राथमिकता के आधार पर गवाही देने कोर्ट जाना चाहिए।

रायगढ़ को मिली इंडियन ओवरसीज बैंक की नई सौगात

रायगढ़, एजेंसी।

शहर के चैतन्य नगर स्थित कृष्णा क्राउन कॉम्प्लेक्स में इंडियन ओवरसीज बैंक की नवीन शाखा का लोकार्पण गुरुवार को उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ शासन के वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओ.पी. चौधरी ने फीता काटकर तथा दीप प्रज्वलित कर बैंक की नई शाखा का विधिवत शुभारंभ किया।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि, बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार केवल वित्तीय सेवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास, डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने और आम नागरिकों तक शासन की योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने का सशक्त माध्यम भी है।

कार्यक्रम में इंडियन ओवरसीज बैंक के क्षेत्रीय महाप्रबंधक (रायपुर) गौरी शंकर नायक,सहित जनप्रतिनिधियों, बैंक अधिकारियों एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। समारोह का शुभारंभ अतिथियों के स्वागत एवं पुष्पगुच्छ भेंट के साथ हुआ।

इसके बाद बैंक अधिकारियों ने अतिथियों को शाखा में उपलब्ध आधुनिक बैंकिंग सुविधाओं, डिजिटल सेवाओं तथा विभिन्न ग्राहक हितैषी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी।

नई शाखा में बचत एवं चालू खाते खोलने की सुविधा के साथ इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम सेवा, डिजिटल बैंकिंग, कृषि एवं व्यवसायिक ऋण सहित अनेक आधुनिक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे क्षेत्र के नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और सुगम बैंकिंग सेवाएं स्थानीय स्तर पर ही प्राप्त हो सकेंगी।

वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि, राज्य सरकार वित्तीय समावेशन को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत है। प्रत्येक नागरिक तक सुरक्षित, पारदर्शी और सुलभ बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

राष्ट्रमंडल खेल: मुरली श्रीशंकर ने लॉन्ग जम्प में जीता रजत पदक

मुरली ने बर्मिंघम 2022 में भी रजत पदक जीता था। वह जमैका के पूर्व वर्ल्ड चैंपियन ताजे गेल से पीछे रहे।

ग्लासगो,एजेंसी। ग्लासगो में बुधवार को कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मुरली श्रीशंकर ने पुरुष लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल जीता। यह लगातार दूसरे राष्ट्रमंडल खेलों में उनका दूसरा पदक था। 27 साल के मुरली श्रीशंकर ने 8.09 मीटर की अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश की। मुरली ने बर्मिंघम 2022 में भी रजत पदक जीता था। वह जमैका के पूर्व वर्ल्ड चैंपियन ताजे गेल से पीछे रहे, जिन्होंने स्कॉटस्टाउन स्टेडियम ट्रैक पर 8.15 मीटर की दूरी तय की थी। स्कॉटलैंड के स्टीफन मैकेंजी ने 8.08 मीटर के साथ कांस्य पदक जीता। आधे मुकाबले तक श्रीशंकर आगे चल रहे थे, लेकिन चौथे राउंड में गेल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विजयी छलांग लगाई।

भारतीय एथलीट श्रीशंकर के छह प्रयासों में 8.03 मीटर, 8.09 मीटर, दो फाउल, 7.94 मीटर और 7.97 मीटर शामिल रहे। इस स्पर्धा में भाग लेने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी लोकेश सत्यनाथन ने कॉमनवेल्थ गेम्स में अपने पहले ही मैच में 7.97 मीटर की सर्वश्रेष्ठ छलांग लगाकर पांचवां स्थान प्राप्त किया। यह पदक श्रीशंकर की वापसी में एक और अहम पड़ाव था। घुटने की चोट के कारण वह पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए कोटा हासिल करने के बावजूद उसमें हिस्सा नहीं ले पाए थे।

हालांकि, ग्लासगो जाने से पहले वह शानदार फॉर्म में थे और उन्होंने सीजन का अपना सर्वश्रेष्ठ 8.38 मीटर का जंप लगाया था। राष्ट्रमंडल खेलों में लॉन्ग जंप में भारत का यह पांचवां मेडल था। हालांकि, श्रीशंकर अकेले ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने दो बार पोडियम पर जगह बनाई है। इस इवेंट में पदक जीतने वाले अन्य भारतीय एथलीट सुरेश बाबू (मेंस ब्रॉन्ज, 1978), अंजू बॉबी जॉर्ज (वूमेंस ब्रॉन्ज, 2002) और प्रजुषा मलियाक्कल (वूमेंस सिल्वर, 2010) हैं।

ग्लासगो 2026 में एथलेटिक्स में भारत का यह तीसरा पदक था। इससे पहले सर्वेश कुशारे ने हाई जंप में और गुलवीर सिंह ने 10000 मीटर रेस में रजत पदक जीता था। वहीं, नेशनल रिकॉर्ड होल्डर पारुल चौधरी महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपलचेज रेस में 9:26.75 के समय के साथ पांचवें स्थान पर रहीं। केन्या की पेरिस 2024 ब्रॉन्ज मेडलिस्ट फेथ चेरोटिच ने 9:01.76 के गेम्स रिकॉर्ड के साथ यह इवेंट जीता। उनके बाद इंग्लैंड की एलिस थोरनर (9:05.45) और युगांडा की पेरुथ चेमुताई (9:09.96) ने पोडियम पर जगह बनाई।

पारुल के पास पोडियम पर जगह बनाने का एक और मौका होगा, जब वह गुरुवार को 5000 मीटर रेस में हिस्सा लेंगी। भारत की मनप्रीत कौर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिला शॉट पुट में मेडल जीतने से मामूली अंतर से चूक गईं। उन्होंने 17.49 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ चौथा स्थान हासिल किया। कनाडा की सारा मिटन ने 19.88 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। नाइजीरिया की जेसिका ओजी ने 17.87 मीटर के साथ रजत पदक हासिल किया, जबकि जमैका की लॉयड्रिशिया कैमरन ने ओजी के बराबर दूरी तय करने के बावजूद काउंटबैक नियम के कारण कांस्य पदक जीता।

नीरज की अगुवाई में तीन एथलीट भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंचे

ग्लासगो,एजेंसी। नीरज चोपड़ा की अगुवाई में भारत के तीन एथलीटों ने गुरुवार को शानदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रमंडल खेल 2026 की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल जगह बना ली है। श्रीलंका के रुमेश थरंगा पाथिराज क्वालिफिकेशन राउंड में शीर्ष पर रहे। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यश वीर सिंह के शुक्रवार को होने वाले 12 खिलाड़ियों के फाइनल में पहुंचने के साथ, भारत तीन एथलीटों को क्वालिफाई कराने वाला एकमात्र देश बन गया। इससे गेम्स के प्रमुख एथलेटिक्स स्पर्धा में से एक में कई पदक जीतने की भारत की उम्मीदें बढ़ गई हैं। पाथिराज 82.84 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ क्वालिफिकेशन में चौंकाने वाले एथलीट बनकर उभरे।

उन्होंने ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स (81.29 मीटर), दक्षिण अफ्रीका के डौव स्मिट (80.64 मीटर) और इंग्लैंड के बेन ईस्ट (80.38 मीटर) को पीछे छोड़ा। तेज हवाओं के कारण थ्रो की दूरी सीमित रही और कोई भी एथलीट 84 मीटर के ऑटोमैटिक क्वालिफाइंग मार्क तक नहीं पहुंच सका। 2018 में स्वर्ण पदक जीतने के बाद अपने पहले राष्ट्रमंडल खेल में हिस्सा ले रहे नीरज ने फाइनल में पहुंचने के लिए जरूरी प्रदर्शन किया। 76.28 मीटर के शुरुआती थ्रो के बाद, भारतीय खिलाड़ी ने अपनी दूसरी कोशिश में 79.61 मीटर का थ्रो किया और कुल मिलाकर पांचवें स्थान पर रहे। उन्होंने अपनी पूरी क्षमता दिखाए बिना ही फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली।

रोहित यादव ने धीरे-धीरे अपनी लय हासिल की और 78.37 मीटर का थ्रो करके नौवां स्थान हासिल किया, जबकि यश वीर सिंह ने 73.89 मीटर के साधारण शुरुआती थ्रो से वापसी करते हुए 78.36 मीटर का थ्रो किया। यह प्रदर्शन उन्हें 10वें स्थान और पदक राउंड में जगह दिलाने के लिए काफी था। पाकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम का प्रदर्शन भी औसत रहा। उनका 78.63 मीटर का शुरुआती थ्रो ही उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो रहा, क्योंकि बाद की कोशिशों में वे इसमें सुधार नहीं कर सके और सातवें स्थान पर क्वालिफाई किया।

गावित ने जीता स्वर्ण, श्रीशंकर को मिला रजत

ग्लासगो,एजेंसी। भारतीय एथलीट दिलीप गावित ने पुरुषों की टी-47 100 मीटर पैरा एथलेटिक्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। वहीं लंबी कूद में मुरली श्रीशंकर ने लगातार दूसरे कॉमनवेल्थ गेम्स रजत पदक अपने नाम किया। दिलीप गावित ने पुरुषों की टी-47 100 मीटर दौड़ में 10.71 सेकंड का समय लेकर गेम्स रिकॉर्ड और सीजन का अपना सर्वश्रेष्ठ समय बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। वहीं, उनके साथी मोहम्मद बासिल मोर्सिंगनाकथ ने 10.83 सेकंड का समय लेकर रजत पदक जीता।

इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के साथ, दिलीप महादु गावित पैरा एथलेटिक्स में कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट बन गए। साथ ही, महिला शॉट पुट एफ 57 इवेंट में शर्मिला के गोल्ड मेडल के बाद, राष्ट्रमंडल खेल पैरा एथलेटिक्स में पदक जीतने वाले वे कुल मिलाकर दूसरे भारतीय पैरा एथलीट हैं।

एथलेटिक्स में, मुरली श्रीशंकर ने पुरुषों की लंबी कूद में 8.09 मीटर की सर्वश्रेष्ठ छलांग के साथ रजत पदक अपने नाम किया और बर्मिंघम 2022 की अपनी उपलब्धि को दोहराया। साथी भारतीय लोकेश सत्यनाथन 7.97 मीटर के साथ पांचवें स्थान पर रहे। पैरा एथलेटिक्स में, सागर थायत और देवेंद्र कुमार पुरुषों की डिस्कस थ्रो एफ42-44/एफ61-64 फ़ाइनल में

अजिंक्य रहाणे ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया

नई दिल्ली,एजेंसी। भारत और मुंबई के बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। रहाणे ने गुरुवार को सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम के जरिए अपने संन्यास की घोषणा की। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो में कहा, मैंने अपनी बल्लेबाजी में हमेशा टाइमिंग पर भरोसा किया है और इसकी अहमियत को हमेशा समझा है। आज मुझे लगता है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का यही सही समय है।

एक छोटे लड़के के रूप में डोंबिवली से यहां तक पहुंचने में मैंने इस खेल को अपना सब कुछ दिया है। हर दिन, हर पारी और बल्लेबाज़ी का हर अवसर मेरे लिए केवल एक सपना लेकर आता था- भारतीय कैप पहनना। मैंने हमेशा एक ही सिद्धांत अपनाया कि देश और टीम को स्वयं से ऊपर रखना है। मैंने यह खेल पूरी ईमानदारी के साथ खेला है और मेरा हमेशा से मानना रहा है कि अगर आपकी नीयत सही हो, तो यह खेल हमेशा आपका साथ देता है। उन्होंने कहा, जब मैंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण किया था।

तब से भारतीय क्रिकेट ने जबरदस्त तरक्की की है। पिछले 20 वर्षों में इस सफर का हिस्सा बनना मेरे लिए बेहद गर्व की बात है। एक भारतीय क्रिकेटर के रूप में मेरा अध्याय अब समाप्त हो रहा है, लेकिन क्रिकेट के साथ मेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं अगली पीढ़ी की मदद करने, इस खेल से सीखे गए मूल्यों को उनके साथ साझा करने और इस खेल को कुछ लौटाने के लिए उत्सुक हूं। रहाणे ने भारत के लिए 85 टेस्ट, 90 वनडे और 20 टी-20 खेले। उनका आखिरी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला जुलाई 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला गया टेस्ट मैच था।

रहाणे के करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक 2020-21 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत को 2-1 से ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जिताना है। इस जीत की सबसे खास बात यह थी कि ऐडिलेड में पहले टेस्ट में भारत के 36 रन पर ऑलआउट होने के बाद रहाणे की कप्तानी में भारतीय टीम ने शानदार वापसी की थी। रहाणे ने 2011 से 2023 तक फैले 12 साल के अंतरराष्ट्रीय करियर का अंत 85 टेस्ट में 38.46 की औसत से 5077 रन और 12 शतकों के साथ किया। वनडे में उन्होंने 90 मैचों में 35.26 की औसत से 2962 रन बनाए, जिसमें तीन शतक शामिल रहे। वहीं, 20 T20I में उन्होंने 20.83 की औसत और 113.29 की स्ट्राइक रेट से 375 रन बनाए। उन्होंने छह टेस्ट मैचों भारत की कप्तानी की, जिनमें टीम ने चार मैच जीते, जबकि दो मुकाबले ड्रॉ रहे।

केसरिया रंग में बदला पुरुष हॉकी टीम की जर्सी का रंग

नई दिल्ली,एजेंसी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम की जर्सी का रंग बदल गया है और इसे नीले रंग से बदलकर केसरिया कर दिया गया है। हॉकी इंडिया ने इस बदलाव पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा, हम आपको बताना चाहते हैं कि यूनिफॉर्म का रंग बदलने का फ़ैसला सपोर्ट स्टाफ़ और खिलाड़ियों की सलाह और उनसे विस्तार से बातचीत के बाद लिया गया था। मुख्य वजह तकनीकी थी। देखा गया कि नीली प्लेइंग यूनिफॉर्म, नीली सिंथेटिक प्लेइंग सतह (जो अब इंटरनेशनल हॉकी पिच का स्टैंडर्ड रंग है) के साथ घुल-मिल जाती थी। इस एक जैसे दिखने की वजह से खिलाड़ियों को मैदान पर साफ़-साफ़ देखने में दिक्कत होती थी। हॉकी इंडिया ने कहा, इसे देखते हुए, कोच और खिलाड़ियों ने पीले या केसरिया जैसे दूसरे रंगों का सुझाव दिया।

अच्छी तरह सोचने-विचारने के बाद, केसरिया रंग को फ़ाइनल किया गया। तकनीकी ज़रूरत पूरी करने के अलावा, केसरिया रंग का गहरा महत्व भी है क्योंकि यह हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रंगों में से एक है, जो साहस, त्याग और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि भारतीय हॉकी में जर्सी का रंग बदलना कोई नई बात नहीं है। समय-समय पर, ज़रूरत के हिसाब से राष्ट्रीय टीम की प्लेइंग किट का रंग बदला जाता रहा है। उदाहरण के लिए, 2014 हॉकी वर्ल्ड कप के दौरान टीम की जर्सी का रंग पीला कर दिया गया था।

बिजनेस

मारुति सुजुकी ने गुजरात में शुरू किया चौथा प्लांट

नई दिल्ली,एजेंसी। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने गुरुवार को गुजरात के हंसलपुर स्थित अपने चौथे विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) प्लांट में व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया। इसके साथ ही इस परिसर की वार्षिक उत्पादन क्षमता बढ़कर 10 लाख (1 मिलियन) वाहन हो गई है। यह अब एक ही स्थान पर भारत का सबसे बड़ा यात्री वाहन निर्माण केंद्र बन गया है।

लगातार दूसरे दिन हरे निशान में बंद हुआ बाजार

मुंबई,एजेंसी। वैश्विक बाजार के मिले-जुले संकेतों के बीच गुरुवार के सत्र में भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुआ। यह लगातार दूसरा कारोबारी सत्र है जब प्रमुख बेंचमार्कों सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी देखने को मिली है।

भारत और जर्मनी मिलकर विकसित करेंगे भविष्य की तकनीकें

साझेदारी से एआई और ग्रीन हाइड्रोजन में खुलेंगे नए अवसर।

नई दिल्ली,एजेंसी। भारत और जर्मनी के बीच उद्योग, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग को नई दिशा देने के उद्देश्य से इंडो-जर्मन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईजीसीसी) ने आईजीसीसी इंडस्ट्री डायलॉग 2026 के दूसरे संस्करण का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में दोनों देशों के नीति-निर्माताओं, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट (आरएंडडी) जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। इंडो-जर्मन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईजीसीसी) के महानिदेशक जान नोएथर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत आने के दो सप्ताह बाद उन्होंने इसी मंच पर अपनी पहली आधिकारिक भागीदारी की थी।

पिछले वर्ष आयोजित इस कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए इसे हर वर्ष आयोजित करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि यह मंच भारत और जर्मनी के नीति-निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं और विशेषज्ञों को एक साथ लाता है, जहां दोनों देश नए विचारों का आदान-प्रदान करते हैं, साझेदारी को मजबूत बनाते हैं और सहयोग के नए अवसर तलाशते हैं। मीडिया से बातचीत में जान नोएथर ने बताया कि दो दिन पहले बेंगलुरु में आयोजित स्टार्टअप प्रतियोगिता में करीब 90 स्टार्टअप्स ने हिस्सा लिया, जहां कई नवोन्मेषी तकनीकी समाधान सामने आए। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जर्मनी के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) इकोसिस्टम का प्रमुख फोकस बन चुका है।

भारत और जर्मनी के बीच सहयोग विशेष रूप से रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर केंद्रित है। उनका मानना है कि यदि दोनों देशों के उद्योग और शोध संस्थान मिलकर नई तकनीकों पर काम करें, तो उनके प्रोजेक्ट और उनके परिणाम वैश्विक स्तर पर मिसाल बन सकते हैं। जान नोएथर ने कहा, स्टार्टअप्स को इस क्षेत्र में सक्रिय होने का आह्वान किया गया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दो दिन पहले ही हमने बेंगलुरु में एक स्टार्टअप प्रतियोगिता आयोजित की थी, जिसमें 90 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

प्रतियोगिता में कई शानदार और बेहद नवीन उत्पाद प्रदर्शित किए गए। विजेताओं को सियोल में होने वाले अगले एशिया-प्रशांत सम्मेलन में आमंत्रित किया जाएगा, जहां वे सीमेंस, बायर, बीएएसएफ और अन्य प्रमुख निगमों के सीईओ सहित जर्मन उद्योग जगत के नेताओं के सामने अपने उत्पादों और परियोजनाओं को प्रस्तुत करेंगे। इससे आर्थिक संबंधों को और मजबूती मिलेगी। जान नोएथर ने आगे कहा कि जर्मनी में ग्रीन हाइड्रोजन की मांग तेजी से बढ़ रही है। वर्तमान में जर्मनी अपनी लगभग आधी बिजली का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से करता है और अब वह ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर को और विस्तार देना चाहता है।

उन्होंने कहा कि इस दिशा में भारत एक महत्वपूर्ण साझेदार बनकर उभर रहा है। भारत प्रतिस्पर्धी लागत पर ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने की क्षमता रखता है और यही कारण है कि जर्मन कंपनियां भारत के साथ इस क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग बढ़ाने की इच्छुक हैं।

अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में नहीं किया बदलाव, मार्केट पर पड़ा असर

न्यूयॉर्क,एजेंसी। महंगाई के खतरे को देखते हुए अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर को 3.5 फीसदी से 3.75 फीसदी पर बिना किसी बदलाव के रखा है। बुधवार (स्थानीय समय) को हुए इस फैसले से स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट आई। इसमें डॉव जोन्स 1,153 पॉइंट्स या 2.19 फीसदी और एनएएसडीएक्यू 433 पॉइंट्स या 1.74 फीसदी नीचे आ गया।

रेट तय करने वाली फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) में मतभेद था। नौ सदस्यों ने रेट को बिना बदले सामान्य रखने के लिए पक्ष में वोट किया, जबकि तीन ने चौथाई पॉइंट रेट बढ़ाने के लिए दबाव डाला। इन तीन में मिनियापोलिस फेडरल रिजर्व के नील काशकारी भी शामिल थे।

फेड चेयरमैन केविन वार्श ने ब्याज दरों को लेकर चल रही असहमति को अच्छी पारिवारिक बहस बताया। उनका कहना है कि लक्ष्य महंगाई पर काबू पाना है, लेकिन साथ ही अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना और रोजगार बाजार को बढ़ाना भी जरूरी है। वार्श को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेड का प्रमुख नियुक्त किया था। ट्रंप का अपने पूर्व फेड प्रमुख जेरोम पॉवेल से ब्याज दरें घटाने से इनकार करने को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था।

वार्श के ब्याज दर में कटौती न करने के फैसले से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं। वर्तमान समय में महंगाई बढ़ने के संकेत दिख रहे हैं। इस महंगाई का कारण ट्रंप के ईरान युद्ध और अमेरिका और दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को माना जा रहा है है। खाड़ी में चल रहे संघर्ष को महंगाई का एक कारण माना जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में रिपोर्टरों से बातचीत के दौरान वॉर्श का बचाव करते हुए कहा कि वह शानदार काम कर रहे हैं। वहीं, ब्याज दर में कमी ना करने का दोष एफओएमसी पर डाल दिया।

उन्होंने कहा, मुझे पता है कि वह कम ब्याज दर देखना पसंद करेंगे, लेकिन उनके पास एक बोर्ड है और यह एक पॉलिटिकल बोर्ड है और वे रेट को ऊपर रखना चाहते हैं। मई में पदभार संभालने के बाद से यह दूसरी बार था जब वार्श एफओएमसी की रेट-सेटिंग मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे और रेट फिर से स्थिर रहे। सितंबर में होने वाली अगली मीटिंग नवंबर में होने वाले मिड-टर्म चुनाव से पहले आखिरी मीटिंग होगी।

भारत में क्रिटिकल मिनरल की मांग 2047 तक 10 गुना बढ़ने की उम्मीद : रिपोर्ट

नई दिल्ली। भारत में क्रिटिकल मिनरल की मांग 2047 तक चार से दस गुना तक बढ़ सकती है। इसकी वजह सरकार की ओर से 2030 तक 500 गीगावाट की गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाने की दिशा में उठाए जा रहे कदम हैं। यह जानकारी गुरुवार को जारी रिपोर्ट में दी गई। ग्रांट थॉर्नटन भारत की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इकोसिस्टम के तेजी से विस्तार के चलते लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, ग्रेफाइट, तांबा और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की मांग में तेज बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अकेले ईवी बैटरियों की मांग 2030 तक 110-130 गीगावाट तक पहुंच सकती है। वहीं, भारत के 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने के साथ क्रिटिकल मिनरल की मांग चार से दस गुना तक बढ़ सकती है।रिपोर्ट के अनुसार, भारत को केवल खनिज संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि एक्सप्लोरेशन, रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग, रीसाइक्लिंग और फंडिंग जैसे क्षेत्रों में मजबूत घरेलू क्षमताएं भी विकसित करनी होंगी।

रिपोर्ट में 'विकसित भारत 2047' के विजन के अनुरूप लक्षित नीतिगत सुधारों, रणनीतिक निवेश और वैश्विक साझेदारियों के माध्यम से वर्ष 2047 तक के लिए तीन चरणों वाला रोडमैप प्रस्तुत किया गया है।पहला चरण 2026-31 के दौरान बुनियादी ढांचा तैयार करने का है, जिसमें एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी (ईपीआर), सर्कुलर मिनरल प्रोसेसिंग जोन तथा बैटरी ट्रेसबिलिटी और रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन शामिल हैं।

दूसरे चरण (2031-36) में रीसाइक्लिंग और ट्रेसबिलिटी प्रणालियों का विस्तार तथा ग्रीन फाइनेंसिंग को बढ़ावा देकर औद्योगिकीकरण को गति देने की बात कही गई है।तीसरे चरण (2036-47) में रणनीतिक आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि आयात पर निर्भरता कम हो, घरेलू रिफाइनिंग और रीसाइक्लिंग क्षमता मजबूत बने तथा 10-15 अरब डॉलर की वार्षिक रीसाइक्लिंग अर्थव्यवस्था विकसित की जा सके।रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़ी नीतियों का फोकस राजस्व अधिकतम करने के बजाय संसाधन सुरक्षा पर होना चाहिए।

भारत में वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में सोने की मांग 6 प्रतिशत घटी

मुंबई,एजेंसी। भारत में वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही (क्यू2) यानी अप्रैल-जून तिमाही के दौरान सोने की कुल मांग में सालाना आधार पर 6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (डब्ल्यूजीसी) की ताजा क्यू2 2026 गोल्ड डिमांड ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार, मौसमी सुस्ती, आयात शुल्क (कस्टम ड्यूटी) का असर और उपभोक्ताओं की बदलती सोच के कारण सोने की खरीदारी प्रभावित हुई। हालांकि, निवेश के उद्देश्य से सोने की मांग अपेक्षाकृत मजबूत बनी रही।

रिपोर्ट के मुताबिक, अप्रैल-जून तिमाही में देश की कुल सोने की मांग 131.4 टन रही, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 139.7 टन थी।

इस दौरान सबसे अधिक गिरावट आभूषणों (ज्वेलरी) की मांग में देखने को मिली। आंकड़ों के अनुसार, ज्वेलरी की मांग सालाना आधार पर 15 प्रतिशत घटकर 88.8 टन से 75.1 टन रह गई। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से गैर-जरूरी सोने की खरीदारी को कुछ समय के लिए टालने और बचत के वैकल्पिक साधनों पर विचार करने की अपील की थी। उनका कहना था कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और आयात लागत में वृद्धि के कारण विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने मई में कहा था, मैं लोगों से अपील करूंगा कि वे एक वर्ष तक शादियों के लिए सोना न खरीदें। यह अपील पश्चिम एशिया में जारी तनाव और उससे पैदा हुई वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच की गई थी। इस बीच, गुरुवार को एमसीएक्स पर मुनाफावसूली के चलते सोने और चांदी की कीमतों में 1 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई। निवेशकों ने अमेरिकी फेडरल रिजर्व (यूएस फेड) की मौद्रिक नीति के फैसले से पहले मुनाफावसूली की। बाजार विश्लेषकों का कहना है कि 4,080 डॉलर के आसपास सोने की कीमतों का टिके रहना इस बात का संकेत है कि बाजार एक ओर सख्त मौद्रिक नीति और दूसरी ओर पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है।

विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने महंगाई पर नियंत्रण के लिए ब्याज दरों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया है और सितंबर में दरों में तत्काल बढ़ोतरी की संभावना भी कम कर दी है। इसके बावजूद वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग फिर से बढ़ सकती है। हालांकि, बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी फेड का 2 प्रतिशत महंगाई लक्ष्य हासिल करने के लिए सख्त रुख अल्पकाल में सोने की कीमतों के लिए चुनौतीपूर्ण माहौल बना सकता है।

एक्ट्रेस से अब प्रेजेंटर बनीं सोनाली बेंद्रे

फिल्म 'सोलह' से शुरू किया सिनेमा का नया सफर

मुंबई। बॉलीवुड में कई सालों तक अपनी खूबसूरती और दमदार एक्टिंग से दिल जीतने वाली सोनाली बेंद्रे अब एक नए रोल में नजर आएंगी। दरअसल, वह अब अभिनय के साथ-साथ अच्छी कहानियों को आगे बढ़ाने का काम भी करना चाहती हैं। इसी सोच के साथ उन्होंने फिल्म 'सोलह' के साथ प्रेजेंटर के तौर पर अपना सफर शुरू किया है। बता दें कि प्रेजेंटर का मतलब होता है वो शख्स जो किसी फिल्म को दर्शकों तक पहुंचाने में मदद करे। वो फिल्म का चेहरा बनता है और लोगों को बताता है कि ये कहानी क्यों जरूरी है। सोनाली अपने इस रोल को लेकर काफी उत्साहित हैं।

आईएएनएस से खास बातचीत में सोनाली बेंद्रे ने बताया कि 'सोलह' उनके लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं है। ये उनके जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत है। उन्हें हमेशा से ऐसी कहानियां पसंद रही हैं जो फिल्म खत्म होने के बाद भी आपके साथ रहें। ऐसी कहानियां जो आपको एक जगह बैठकर सोचने पर मजबूर कर दें। 'सोलह' में ये सब है, इसलिए जब उन्होंने पहली बार इस फिल्म की कहानी सुनी तो वो तुरंत उससे जुड़ गईं।

सोनाली ने कहा, "फिल्म को प्रेजेंट करना मेरे लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि यह मेरे लिए एक नए सफर की शुरुआत है। मैंने हमेशा ऐसी कहानियों को चुना है जो खत्म होने के बाद भी आपके दिल और दिमाग में रह जाती हैं। जो आपको थोड़ी देर के लिए रुककर सोचने पर मजबूर करती हैं। आपको जिंदगी को थोड़ा अलग तरीके से देखने में मदद करती हैं। 'सोलह' ने मेरे साथ बिल्कुल यही किया। इसे सुनने के बाद मैं काफी देर तक शांत रही और सोचती रही।"

सोनाली ने बताया कि आखिर उन्हें 'सोलह' की कहानी इतनी क्यों पसंद आई। उन्होंने कहा, "जब मैंने पहली बार कहानी सुनी तो वो सीधे मेरे दिल से जा लगी। असल में ये फिल्म उम्मीद की कहानी है। ये हिम्मत की कहानी है और सबसे जरूरी बात ये आम लोगों के अंदर छिपी उस शांत ताकत की कहानी है, जिसके बारे में हम रोजमर्रा की जिंदगी में बात नहीं करते। पिछले कुछ सालों में मैंने जिंदगी को बहुत करीब से देखा है। बीमारी, संघर्ष और फिर उससे उबरना। इन सबके बाद मैंने उम्मीद और हिम्मत की कीमत और भी ज्यादा समझी है। इसलिए मुझे लगता है कि अपने इस नए सफर की शुरुआत के लिए 'सोलह' सबसे सही फिल्म है।"

जब आईएएनएस ने उनसे पूछा कि एक प्रेजेंटर के तौर पर उनका क्या मकसद है, तो इस पर सोनाली ने कहा, "अब जब मैं एक प्रेजेंटर के तौर पर ये सफर शुरू कर रही हूं, तो मेरी सबसे बड़ी इच्छा यही है कि मैं ऐसी फिल्मों को सपोर्ट करूं जो लोगों के दिल को छूएं, जो लोगों को इमोशनली हिला दें।

साथ ही मैं चाहती हूं कि दर्शकों को ऐसे नए कहानीकार मिलें, ऐसे नए डायरेक्टर मिलें, जिनकी आवाज अब तक लोगों तक नहीं पहुंची है, लेकिन उनकी कहानियां सुनने लायक हैं। मुझे लगता है कि 'सोलह' से बेहतर शुरुआत मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती थी। मुझे उम्मीद है कि जब लोग सिनेमाघर से बाहर निकलेंगे, तो उन्हें भी ठीक वैसा ही महसूस होगा जैसा मुझे हुआ था।"'सोलह' को रोज मूवीज और कैरीऑन पिक्चर्स ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। फिल्म 16 अक्टूबर को पूरे देश में सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

'लॉक अप 2' में नेहल ने बढ़ाया आकांक्षा चमोला का हौसला

बोलीं-अपनी असली पर्सनालिटी दिखाओ

मुंबई। पूर्व बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट और मॉडल नेहल चुडासमा टीवी की दुनिया का जाना-पहचाना नाम हैं। बिग बॉस के घर में भी उन्होंने कई बार गलत समझे जाने और अकेले पड़ जाने का दर्द झेला था। शायद इसी वजह से जब वो 'लॉक अप 2' में आकांक्षा चमोला को सपोर्ट करने विजिटर बनकर पहुंचीं, तो उन्होंने सबसे पहले आकांक्षा की उसी उलझन को पकड़ा जो पिछले कई दिनों से दर्शकों को भी खटक रही थी।

'लॉक अप 2' में आकांक्षा चमोला पिछले कुछ समय से काफी शांत नजर आ रही थीं। शो में एंट्री के समय जितनी एनर्जी और कॉन्फिडेंस उनमें था, धीरे-धीरे वो गायब होता चला गया। दर्शकों को लग रहा था कि आकांक्षा गेम नहीं खेल रही हैं, बस कोने में बैठकर सब सह रही हैं। इसी बीच नेहल की एंट्री हुई और उन्होंने आते ही आकांक्षा से बातें की।

नेहल ने आकांक्षा से कहा कि उन्होंने गौरव खन्ना की सलाह को गलत तरीके से ले लिया है। उन्होंने कहा, "मुझे पता है गौरव अच्छी नीयत से आया था, लेकिन मुझे लगता है आपने उसकी बातों के सिर्फ गलत हिस्से पकड़े और खुद को समेट लिया। आपको गलत समझा गया है। मैं खुद रियलिटी शो में कई महीनों तक गलत समझी गई थी, इसलिए ये फीलिंग मैं जानती हूं कि जब पूरी दुनिया आपको गलत समझे तो कैसा लगता है।"

नेहल ने आकांक्षा से कहा, "अब आपको इस खेल से बाहर निकलना होगा और अपनी असली पर्सनालिटी दिखानी होगी। इस समय 'लॉक अप 2' जितने लोग देख रहे हैं, उसकी बड़ी वजह आकांक्षा के सीक्रेट्स हैं।"

जुलाई के पहले हफ्ते में आकांक्षा ने बताया था कि शादी से पहले वह बाइसेक्सुअल थीं। उनका कुछ लड़कियों के साथ रिलेशन रहा है, हालांकि उन्होंने साफ किया था कि वो रिलेशन में बहुत ज्यादा इंटीमेट नहीं थीं। आकांक्षा ने यह भी कहा था कि उनके लिए महिलाएं सेफ स्पेस हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया मर्दों की है, इसलिए लड़कियां बचपन से ही अपनी मां और बहनों के करीब होती हैं और वहीं उन्हें सबसे ज्यादा कम्फर्ट मिलता है।

'सुपर 30' में ऋतिक रोशन के अभिनय ने मुझे काफी प्रभावित किया था : हिमांश कोहली

मुंबई। अभिनेता हिमांश कोहली फिल्म 'आर्यभट्ट का जीरो' के साथ सिनेमाघरों में धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। अभिनेता ने आईएएनएस के साथ बातचीत में बताया कि उन्हें ऋतिक रोशन की फिल्म 'सुपर 30' ने किस तरह प्रभावित किया था।

उन्होंने कहा, 'सुपर-30' ने मुझे काफी प्रभावित किया था और उस फिल्म में ऋतिक की परफॉर्मेंस उन्हें उसी तरह पसंद आई थी, जैसे बाकी लोगों को पसंद आई थी। शिक्षक और गणितज्ञ आनंद कुमार का किरदार प्रेरणादायी और दिल को छू लेने वाला था। मैं समझता हूं कि जब आप किसी ग्लैमर को छोड़कर आम नागरिक का किरदार करते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा मुश्किल लोगों को समझाने में लग जाता है कि ये आप ही हैं, और आप इस तरह के रोल भी कर सकते हैं, क्योंकि दर्शक आपको इस तरह के किरदार में स्वीकार नहीं करते और न ही वे चाहते हैं कि आप ऐसे किरदार करें।'

उन्होंने 'सुपर-30' को याद करते हुए कहा, 'इस फिल्म में भी ऋतिक रोशन की परफॉर्मेंस उनके बाकी किरदारों से अलग थी और उस फिल्म की कहानी भी छात्रों के ईर्द-गिर्द थी। उनके संघर्ष और पढ़ाई की कहानी थी, लेकिन हमारी फिल्म की कहानी थोड़ी सी अलग है। इसकी कहानी पूरी तरह से पारिवारिक माहौल के आसपास थी। हालांकि, हमारी कहानी का मुद्दा शिक्षा और छात्रों के संघर्ष पर है। इसमें छात्रों के उसी संघर्ष को दिखाया गया है, जो आज का युवा झेल रहा है।'

विदेश

कुवैत में चीनी कंपनी पर ईरान का हमला

कुवैत सिटी। ईरान के मिसाइल हमले में कुवैत स्थित एक चीनी कंपनी की इमारत निशाना बनी है। कुवैत की सेना के मुताबिक, हमले में एक कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है। कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को इसे लेकर एक बयान जारी किया।

इंग्लैंड में हीट वेव के कारण मृतकों का आंकड़ा बढ़ा

लंदन। यूरोप जुलाई महीने में भी गर्मी से झुलस रहा है। इंग्लैंड में इस वर्ष मई और जून के दौरान पड़ी भीषण गर्मी (हीटवेव) से होने वाली अतिरिक्त मौतों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दोगुनी हो गई है। ब्रिटेन की यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी (यूकेएचएसए) की एक अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार, इस साल अब तक हीटवेव से जुड़ी अनुमानित 2,877 अतिरिक्त मौत दर्ज की गई हैं।

ईरान पर हमले की बारी हमारी है, मिसाइल हमले के बाद ट्रंप ने बदला लेने की कसम खाई

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के समर्थन वाली सेनाओं के एक और हमले के बाद अमेरिका जोरदार जवाब देगा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना द्वारा पांच मिसाइलों को रोकने के बाद अब उन पर हमला करने की हमारी बारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बुधवार (स्थानीय समय) को वाशिंगटन डलेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को फिर से बनाने की घोषणा की।

इसके बाद ट्रंप ने कहा कि उन्हें मिस्र के पास एक एलएनजी टैंकर पर हुए ड्रोन हमले के बारे में जानकारी दी गई थी और उन्होंने संकेत दिया कि वाशिंगटन सैन्य कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है, हालांकि उन्होंने भविष्य में समझौते की संभावना भी खुली रखी।राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, ₹हम उन पर जोरदार हमला करेंगे, क्योंकि अब पलटवार करने

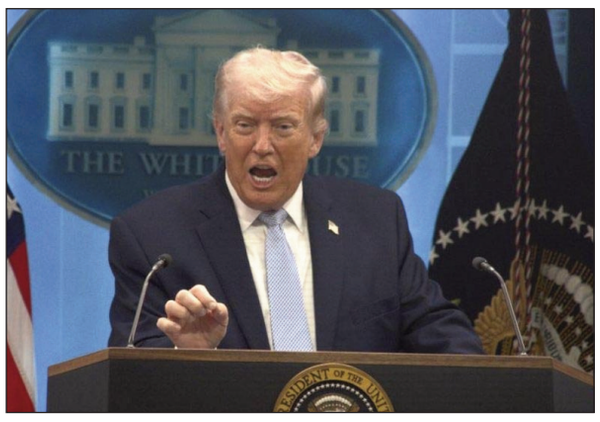

की हमारी बारी है। मुझे पता है कि ऐसा होने वाला है। वे हमें ऐसा न करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन कल रात उन्होंने हमला करने की कोशिश की।

उन्होंने 8,500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पांच रॉकेट दागे गए थे यह अच्छी बात रही कि हमारे लोग दुनिया के सबसे बेहतरीन उपकरण यानी पैट्रियट सिस्टम को ऑपरेट कर रहे थे। उन सभी रॉकेट को जमीन पर गिरा दिया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने हमला करने की कोशिश की, इसलिए अब हमारी बारी है। हम देखेंगे कि क्या कभी कोई समझौता हो पाता है, लेकिन हम उन पर बहुत जोरदार हमला करने वाले हैं।'

ट्रंप ने संकेत दिया कि हमले की उस कोशिश में बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल थीं।यह पूछे जाने पर कि क्या हमला होने पर अमेरिका हमेशा सैन्य तरीके से जवाब देगा, ट्रंप ने जवाब दिया, 'काफी हद तक।'उन्होंने उन सुझावों को भी खारिज कर दिया कि इन हमलों की वजह से वॉशिंगटन को इस इलाके से अपनी सेना हटानी पड़ेगी। उन्होंने कहा, 'मुझे ऐसा नहीं लगता। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे।₹ट्रंप ने कहा कि जिन लोगों ने यह किया, उन्होंने पहले ही तनाव कम करने की कोशिश की है। यह उस ग्रुप से अलग ग्रुप था जिससे हम निपट रहे हैं। उन्होंने पहले ही माफी मांग ली है, लेकिन हमें उन्हें थोड़ा सबक सिखाना होगा।'

राष्ट्रपति ने उन खबरों पर भी बात की कि ईरान को पाकिस्तान के जरिए चीन से सैकड़ों रॉकेट लॉन्चर मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो उन्हें हैरानी होगी। ट्रंप ने कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि बीजिंग ईरान को हथियार नहीं देगा और वे जानते हैं कि इससे मुझे बहुत निराशा होगी।यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने युद्ध खत्म करने की अपनी इच्छा फिर से दोहराई। ट्रंप ने कहा, 'बैठक अच्छी रही। राष्ट्रपति पुतिन और जेलेंस्की के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं 'मैंने कहा, बस युद्ध खत्म करो।'ट्रंप ने कांग्रेस से ईरान के खिलाफ लंबित कानून को और मजबूत करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा, 'मैं चाहूंगा कि वे ईरान पर सिर्फ प्रतिबंध ही नहीं, बल्कि टैरिफ भी लगाएं। मुझे लगता है कि यह जरूरी है।'

पाकिस्तानः लाहौर में इमारत गिरने से 11 लोगों की मौत

नई दिल्ली। लाहौर में बुधवार रात दर्दनाक हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय मीडिया की गुरुवार की रिपोर्ट के अनुसार, लाहौर के हरबंसपुरा इलाके में बीती रात एक तीन मंजिला इमारत गिर गई। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई और छह अन्य लोग घायल हो गए। पाकिस्तान के अखबार डॉन की रपिोर्ट के अनुसार, लाहौर के डिप्टी कमिश्नर के प्रवक्ता हैरिस अली ने बताया कि मलबे से लोगों के शव निकाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बचावकर्मी अभी भी मौके पर डटे हुए हैं। लोगों का कहना है कि एक छोटी बच्ची अभी भी मलबे के फंसी हुई है।प्रवक्ता के अनुसार, इस इमारत में तीन भाई अपने परिवारों के साथ रहते थे।

होर्मुज को पार कर गया कतर एनर्जी का एलएनजी टैंकर

दोहा। पश्चिम एशिया टकराव के बीच होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले टैंकरों या जहाजों की संख्या काफी कम हो गई है। इस बीच कतर एनर्जी के नियंत्रण वाला एक लिक्विफाइड नैचुरल गैस (एलएनजी) टैंकर (बुधवार-गुरुवार की रात) होर्मुज से सफलतापूर्वक गुजर गया। जहाजों की निगरानी करने वाली कंपनियों के आंकड़ों के अनुसार, 11 जुलाई के बाद यह पहला कतर एनर्जी-नियंत्रित एलएनजी पोत है जिसने इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से बाहर निकलने में सफलता पाई।

केप्लर और एलएसईजी के आंकड़ों के मुताबिक,अल अरीश नामक टैंकर ने 4 से 6 जुलाई के बीच कतर के रस लाफान टर्मिनल से एलएनजी का कार्गो लोड किया था और 29 जुलाई की रात होर्मुज जलडमरूमध्य से बाहर निकल गया।एलएसईजी के आंकड़ों के अनुसार, यह टैंकर फिलहाल पाकिस्तान के पोर्ट कासिम की ओर बढ़ रहा है।

संयुक्त अभ्यास के दौरान यूएस ड्रोन सीमा क्षेत्र में घुसा, दक्षिण कोरिया ने खाली कराए कई इलाके

सोल। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच कोरियाई प्रायद्वीप में संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा है। गुरुवार को अमेरिकी मिलिट्री ड्रोन ने सीमा क्षेत्र को पार कर लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एहतियातन पास के इलाकों को खाली कराया गया और वहां के निवासियों को कहीं और शिफ्ट किया गया।

दोनों पक्षों के सैन्य अधिकारियों के अनुसार, उत्तर कोरिया की सीमा से सटे उत्तरी ग्योंगगी प्रांत में एक जनरल आउटपोस्ट के दक्षिण में यूएवी (मानव रहित हवाई वाहन) का पता चला था। बाद में इसकी पहचान यहां तैनात यूएस मरीन कॉर्प्स के एक मिलिट्री ड्रोन के रूप में की गई।दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ (जेसीएस) के एक अधिकारी ने पत्रकारों को बताया, 'आगे की जांच-पड़ताल के बाद, इस यूएवी की पहचान ट्रेनिंग में शामिल यूएस मिलिट्री ड्रोन के रूप में की गई।'

योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, जेसीएस अधिकारी ने कहा कि इसके बाद तय प्रोटोकॉल के अनुसार ऑपरेशनल कदम उठाए गए।यूएस फोर्सेज कोरिया (यूएसएफके) ने भी पुष्टि की कि यह उनका ही ड्रोन था और कहा कि वे स्थिति का आकलन करने के लिए दक्षिण कोरियाई अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।यूएसएफके ने दक्षिण कोरिया का आधिकारिक नाम लेते हुए कहा, 'यह घटना यूएस मरीन और रिपब्लिक ऑफ कोरिया मरीन कॉर्प्स के फर्स्ट मरीन डिवीजन के बीच द्विपक्षीय प्रशिक्षण के दौरान हुई।'

उन्होंने आगे कहा, 'यूएस मरीन कॉर्प्स के कर्मी घटना से जुड़ी परिस्थितियों का आकलन कर रहे हैं और रिपब्लिक ऑफ कोरिया मरीन कॉर्प्स के हमारे सहयोगियों और संबंधित स्थानीय अधिकारियों के साथ संपर्क साधे हुए हैं।'

इससे पहले दिन में, सोल से लगभग 70 किलोमीटर उत्तर में, उत्तर-दक्षिण कोरियाई सीमा के साथ बफर जोन के पास चेओरवोन में एक अलर्ट जारी किया गया था, जिसमें इलाके के निवासियों को सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी गई थी क्योंकि ड्रोन की उड़ान का पता चला था।दक्षिण कोरियाई सेना ने सबसे पहले अपने निगरानी उपकरणों के माध्यम से ड्रोन का पता लगाया, लेकिन जाहिर तौर पर वे तुरंत यह पता नहीं लगा पाए कि क्या ड्रोन उत्तर कोरिया से आया हो सकता है।ड्रोन की उड़ान के तरीके को देखते हुए, हो सकता है कि इसकी नियोजित उड़ान की जानकारी क्षेत्र में दक्षिण कोरियाई सैन्य इकाइयों के साथ साझा न की गई हो।